● वर्ष-4
● अंक-152
रायपुर, मंगलवार
04 फरवरी 2025
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

# समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» घर में सुख-शांति और सकारात्मकता के लिए....

# भाजपा के घोषणा पत्र में नगरों विकास के लिए साय सरकार की गारंटी

## महिलाओं को प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट , नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून

**रायपुर।** प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री साय ने अटल विश्वास पत्र का विमोचन करते हुए कहा कि अटल विश्वास पत्र नगरीय निकाय क्षेत्र के भविष्य को तय करने का संकल्प है। आने वाले समय में नगरीय निकाय क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा जो काम करने वाली है, वह अटल विश्वास पत्र के रूप में हमारे सामने है। श्री साय ने कहा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में पूरे प्रदेश में अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, उसके चलते कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी थी। कांग्रेस ने प्रदेश के हर वर्ग के साथ कांग्रेस की सरकार ने छलावा किया था। इसलिए 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास करते हुए एक बड़ा देश जनादेश भाजप को दिया। मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने का काम प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया है। अटल विश्वास पत्र में जो भी वादा सरकार ने किया है, वह शत-प्रतिशत पूरा होगा।

घोषणा पत्र समिति के प्रदेश संयोजक एवं विधायक अमर अग्रवाल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अटल विश्वास पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित है।

### अटल विश्वास पत्र के प्रमुख बिंदु

- ♦ नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही, हम सभी पट्टा धारकों को भू- स्वामी बनाएंगे।
- ♦ रुके हुए पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं को, और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख पीएमएवाय-घरों को तेजी से पूरा करेंगे। इसके साथ ही, जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते है, उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी।
- ♦ महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10% की विशेष छूट प्रदान करेंगे।
- ♦ प्रत्येक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- ♦ प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करेंगे।
- ♦ बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार करेंगे, ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके।
- ♦ विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
- ♦ स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, हम स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन, फूड स्ट्रीट्स की स्थापना करेंगे और एक समुचित नीति बनाएंगे, जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- ♦ समाधान योजना के माध्यम से हम बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान प्रदान करेंगे।

10. विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

- ♦ स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के स॥ल लाभार्थियों को ?2.5 लाख तक का ऋ्रा और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने।
- ♦ यूजर चार्ज का युक्त युक्तिकरण करेंगे।
- ♦ स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे।
- ♦ माई सिटी ऐप लॉन्च करेंगे, जो नगर निगम की सभी ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। हम हर ज़ोन में एक एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि लोगों को बार बार निगम दफ्तर नहीं जाना पड़े।
- ♦ हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे, नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे।
- ♦ छत्तीसगढ़ को सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीज़ों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे।
- ♦ प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और इसे एस.टी.पी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जोड़ेंगे ताकि तालाबों की स्वच्छता हो सके।
- ♦ गोकुल नगर का विस्तार करेंगे, ताकि गोवंश संरक्षण, उनकी देखभाल और आवास के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
- ♦ शहरों में शासकीय जगहों पर कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण करेंगे, जिससे यातायात पार्किंग की समस्याओं और जाम का समाधान सुनिश्चित होगा।
- ♦ प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में सीटों की संख्या भी बढ़ाएंगे।

### ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल सह संयोजक सुनील सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी संजय श्रीवास्तव, राकेश पाण्डेय, चंद्रशेखर साहू, मोतीलाल साहू, प्रबोध मिंज, नीलकंठ टेकाम, रिकेश सेन, प्रदेश दीपक म्हस्के, पंकज झा,अमित चिमनानी श्रीमती अम्बिका यदु, शशांक शर्मा, उज्जवल दीपक, हेमंत पाणिग्रही, प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश चंद्र गुप्ता, आदि उपस्थित रहे।

## नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन

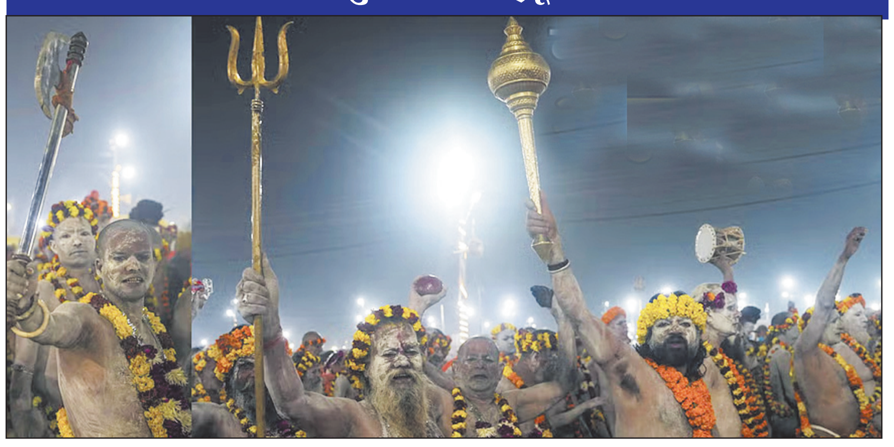

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान में नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। त्रिवेणी घाट पर इन साधुओं की पारंपरिक और अद्वितीय गतिविधियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

# दिल्ली में थमा चुनाव प्रचार का शोर, 5 फरवरी को मतदान

**नईदिल्ली।** दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, जिसकी मतगणना 8 फरवरी को होगी और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। दिल्ली के चुनावी रण में कुल 699 उम्मीदवार अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी जोर-शोर से जुटे रहे। दिल्ली में चुनावी शोर 3 फरवरी को शाम 5 बजे से थम गया। इसके बाद कोई भी उम्मीदवार चुनाव प्रचार नहीं कर सकेगा। बता दें कि मतदान के लिए 2696 मतदान स्थलों पर 13,766 बूथ बनाए गए हैं। मतदाताओं को बूथ परिसरों में आसानी से अपने मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए सभी जिला चुनाव अधिकारी रंग कोड के अनुसार केंद्र स्थापित करेंगे।

**27 साल बाद सत्ता में आने की चाहत:**राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 27 साल से सत्ता हासिल करने के लिए कड़े प्रयास कर रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिल्ली में कुल 22 रोड शो और रैलियां की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जनता का मूड बता रहा है कि 5 फरवरी को दिल्ली में कमल खिलने जा रहा हैज्मैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के लिए बहुत समय दिया।

पिछले दो चुनावों से दिल्ली में आम

आदमी पार्टी ने अपना कब्जा बनाया हुआ है और फिर से सत्ता हासिल करने के लिए इस बार भी,क्कके वरिष्ट नेताओं ने चुनाव-प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। वहीं 15 साल सत्ता संभालने वाली कांग्रेस पिछले दो चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई। हालांकि, इस बार कांग्रेस पिछले दो बार का सूखा खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करती नजर आई।

### दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या

दिल्ली में कुल 1.55 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 83.49 लाख पुरुष और 71.73 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा, थर्ड जेंडर के 1,261 मतदाता भी हैं। युवा मतदाताओं की संख्या 25.89 लाख है। दिल्ली चुनाव में 13,033 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें दिव्यांग और महिलाओं द्वारा प्रबंधित 70-70 केंद्र शामिल हैं।

### दिल्ली पुलिस की व्यवस्था

दिल्ली पुलिस ने विधानसभा चुनाव की सुरक्षा के लिए 150 से अधिक अर्धसैनिक बलों की कंपनियां और 30,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात करने की योजना बनाई है।

## प्रमुख समाचार

### सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

**नईदिल्ली।** भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर उनकी %बेचारी% टिप्पणी को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। संसद की संयुक्त बैठक में अपने संबोधन के दौरान सोनिया गांधी ने

राष्ट्रपति मुमू को पुअर थिंग कहा था, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। 31 जनवरी को संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सदन के बाहर पत्रकारों ने गांधी से मुर्मू के लगभग एक घंटे लंबे भाषण के बारे में पूछा तो पूर्व कांग्रेस प्रमुख को क्लिप में यह कहते हुए सुना गया कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थक गई थी। वह मुश्किल से बोल पा रही थीं, बेचारी। सोनिया गांधी की टिप्पणी से तुरंत भाजपा नेताओं की ओर से निंदा की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति भवन ने भी एक बयान जारी कर टिप्पणी को अस्वीकार्य बताया और कहा कि मुर्मू थके नहीं हैं। बाद में पीएम मोदी ने भी दिल्ली की एक रैली में कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि सोनिया की टिप्पणी से आदिवासी समुदायों का अपमान हुआ है। द्रौपदी मुर्मू जी यहां एक आदिवासी परिवार से आई हैं।

### महाराष्ट्र में चुनाव की निष्पक्षता पर राहुल गांधी का सवाल

**नईदिल्ली।** कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा में बहस के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजों पर सवाल उठाया। उन्होंने महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच पंजीकृत

मतदाताओं में उल्लेखनीय वृद्धि का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र की मतदाता सूची में लगभग 70 लाख नए मतदाता जुड़े। यह हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या जितनी है। शिरडी की एक ही बिल्डिंग में 7 हजार से ज्यादा वोटर जुड़ गए। राहुल गांधी ने कहा, ''मैं इस सदन का ध्यान महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े कुछ डेटा की ओर खींचना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच, हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर लोगों को महाराष्ट्र की मतदान सूची में जोड़ा गया। लगभग 70 लाख नए वोटर अचानक आ गए।'' उनका कहना था कि महाराष्ट्र में जितने वोटर पांच साल में नहीं जुड़े, उससे ज्यादा वोटर पांच महीने में जुड़ गए। राहुल गांधी ने दावा किया, ''शिरडी की एक इमारत में 7,000 वोटर जोड़े गए...दिलचस्प बात यह है।

### अवैध धर्मांतरण रोकने राजस्थान में विधेयक

**नईदिल्ली।** उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर राजस्थान की भाजपा सरकार ने भी अवैध धर्मांतरण रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। हम आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के मकसद से राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध

विधेयक, 2025 सोमवार को विधानसभा में पेश किया है। हम आपको बता दें कि इस विधेयक में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रस्तावित अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अवैध धर्मांतरण विरोधी विधेयक विधानसभा में पेश किया। इसमें गलतबयानी, बल प्रयोग, गलत प्रभाव, उत्पीड़न, प्रलोभन, छल या जबरन शादी के जरिये एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध संपरिवर्तन को अपराध बनाया गया है। विधेयक में कम से कम एक साल के कारावास, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 15,000 रुपये के जुर्माने की सजा देने का प्रावधान किया गया है।

### पीएम के इनविटेशन पर नहीं हुई कोई बात: जयशंकर

**नईदिल्ली।** विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस दावे का जोरदार खंडन किया है कि भारत सरकार ने उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण हासिल करने के

लिए अमेरिका भेजा था। विपक्ष के नेता पर भारत की छवि खराब करने वाली टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान उनके निमंत्रण पर कभी चर्चा नहीं की गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिसंबर 2024 में मेरी अमेरिका यात्रा के बारे में जानबूझकर झूठ बोला। मैं बिडेन प्रशासन के राज्य सचिव और एनएसए से मिलने गया। इसके अलावा, हमारे महावाणिज्यदूतों की एक सभा की अध्यक्षता करने के लिए भी। जयशंकर ने कहा कि मेरे प्रवास के दौरान, आने वाले एनएसए-नामित ने मुझसे मुलाकात की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में बोलते हुए गांधी ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर कटाक्ष किया और आरोप लगाया कि पीएम मोदी को निमंत्रण दिलाने के लिए जयशंकर को अमेरिका भेजना पड़ा।

### तमिलनाडु के मंदिर में तोड़फोड़, ईसाई पुजारी जिम्मेदार

**नईदिल्ली।** तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक मंदिर में मूर्तियां तीसरी बार खंडित पाई गईं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मंदिर के खिलाफ एक ईसाई पुजारी की टिप्पणी ने हमलों को उकसाया। बर्बरता की पहली घटना 25 दिसंबर को दर्ज की गई थी,

जब साजिन नाम के एक व्यक्ति ने वियन्नूर के पास थोट्टुथुविलाई में इसक्कियाम्मन मंदिर की मुख्य मूर्ति को तोड़ दिया था। पुलिस शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालाँकि, 29 दिसंबर को साजिन ने साथियों के एक समूह के साथ, कथित तौर पर मंदिर में फिर से तोड़फोड़ की, परिसर की दीवार को नुकसान पहुँचाया। पुलिस के सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के दौरान, साजिन ने दावा किया है कि एक ईसाई पुजारी ने उसे बताया था कि मंदिर शैतान का निवास था और इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। सबसे हालिया हमला 1 जनवरी को रात करीब 11 बजे हुआ, जब साजिन और पांच अन्य लोगों ने कथित तौर पर मंदिर में प्रवेश किया और और मूर्तियां तोड़ दीं। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिससे समूह भाग गया। सोशल मीडिया पर तोड़े गए।

## संसद समीक्षा

# राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा, राहुल का मोदी सरकार पर वार

**नईदिल्ली।** संसद का बजट सत्र चल रहा है। शनिवार को देश का बजट पेश किया गया था। इसके बाद आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा में आज राहुल गांधी ने सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। वहीं, राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर तंज कसा। इसके अलावा आज दोनों सदनों में कुछ क्षणों के लिए हंगामा भी देखने को मिला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद महाकुंभ में प्रबंधन का मुद्दा उठा रहे थे। इस दौरान विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार ने मरने वालों के आंकड़े छुपाए हैं। हालांकि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लगातार विपक्ष से सदन को चलने देने की अपील की।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को देश के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर और इलेक्ट्रिक वाहन, डेटा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आईए) से जुड़ी आधुनिक युग की क्रांति में भाग लेकर चीन को पछाड़ा जा सकता है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया' को लेकर प्रयास जरूर किया, लेकिन यह विचार विफल रहा क्योंकि विनिर्माण दर घट गई। उन्होंने कहा कि देश बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर पाया है और इस बारे में युवाओं कोई स्पष्ट जवाब देने में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) दोनों की सरकारें विफल रही हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच की कुछ महीनों की अवधि में ही राज्य में हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर मतदाताओं की

संख्या बढ़ गई और ऐसे में निर्वाचन आयोग को प्रदेश के विपक्षी दलों को मतदाता सूची से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराने चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सोमवार को दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) नीत सरकार पर देश की राजधानी को विदेशी लुटेरों महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और अंग्रेज शासकों की तरह लूटने का आरोप लगाया। बिधूड़ी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गत 31 जनवरी को संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए अपने लगभग पूरे भाषण में आम आदमी पार्टी, उसके नेताओं और दिल्ली में पार्टी की सरकार पर निशाना साधा।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने सोमवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 31 जनवरी को संसद के संयुक्त सत्र में दिए गए अभिभाषण में महाकुंभ में भगदड़ की घटना पर मृतकों के परिवारों के प्रति शोक नहीं जताया गया और किसानों की कर्ज माफी पर भी इसमें कुछ नहीं कहा गया।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की एक हालिया टिप्पणी की आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा तथा उनके 'राजनीतिक डीएनए' में है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह भी कहा कि संविधान बचाने की बात करने वालों को पहले राष्ट्रपति पद का सम्मान करना सीखना चाहिए।

### राज्यसभा की कार्यवाही

सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि विमानन कंपनियों को कॉल कर बम की झूठी धमकी देने के मामलों में 2024 में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को राज्यसभा में सरकार पर तीखा हमला बोला और सवाल किया कि यह अमृत काल है या विष काल? राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार 'सबके विकास' की बात करती है लेकिन वह सिर्फ चंद उद्योगपतियों, अमीरों और अपने कुछ दोस्तों का ही विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण किसान और बेरोजगार आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं।

राज्यसभा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला बोलते हुए कहा कि उसकी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को 'डर्टी स्लम' बनाकर ''बदहाल'' कर दिया है और उसके नेता अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए दूसरों पर ''अनाप-शनाप'' आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनका जनाधार पूरी तरह खिसक चुका है।

राज्यसभा में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक सदस्य ने महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और शोषण से जुड़े कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग पर चिंता जताई और झूठे आरोपों का सामना करने वाले पुरुषों के लिए पर्याप्त कानूनी और भावात्मक समर्थन की मांग उठायी।

# पुलिस-नक्सली मुठभेड़, कांकेर में 1 वर्दीधारी माओवादी ढेर

**कांकेर।** नक्सलियों पर सुरक्षाबलों की टीम कहर बनकर टूट रही है, जिसके परिणामस्वरूप नक्सली या तो हथियार डालकर मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं या फिर मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। 1 फरवरी को सुकमा के गंगालूर थाना क्षेत्र के तोड़का के जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं 2 फरवरी को कांकेर जिले के नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र में डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने माओवादी विरोधी अभियान चलाया। इस मुठभेड़ के बाद एक वर्दीधारी पुरुष माओवादी का शव बरामद किया गया, जिसके पास से एक एसएलआर राइफल और अन्य नक्सल सामग्री भी मिली।

मिली जानकारी के अनुसार, 2 फरवरी को दोपहर 12ः30 बजे डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त टीम को प्रतिबंधित माओवादी संगठन अंतर्गत उत्तर बस्तर-माड़ डिवीजन के सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षाबलों ने माओवादी विरोधी अभियान शुरू किया। दोपहर करीब 12ः30 बजे संयुक्त टीम और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुआ। घटनास्थल पर सर्चिंग अभियान चलाने के बाद मौके से 1वर्दीधारी पुरुष माओवादी का शव बरामद हुआ है। साथ ही 1 एसएलआर रायफल और अन्य नक्सल सामग्री भी मिले हैं। मृत नक्सली की पहचान की जा रही है।

मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के मारे जाने अथवा घायल होने की संभावना है। सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है।

## सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह ने नक्सलगढ़ का किया दौरा, नक्सल ऑपरेशन की ली जानकारी

**रायपुर।** सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का जायजा लिया।इसके लिए जीपी सिंह शनिवार को दंतेवाड़ा के सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। इस दौरान शनिवार को बस्तर रेंज के आईजी और सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें कि सीआरपीएफ का पदभार संभालने के तुरंत बाद जीपी सिंह ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया। इस दौरान जीपी सिंह उन शिविरों में भी पहुंचे जहां पर बचे हुए नक्सलियों को खदेड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

शनिवार को सीआरपीएफ डीजी जीपी सिंह ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। तब बीजापुर के गंगालूर जंगल में नक्सलियों और राज्य पुलिस, सीआरपीएफ की 222 बटालियन और 202 कोबरा की संयुक्त टीमों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में आठ नक्सली मारे गए, जिनमें पश्चिमी बस्तर डिवीजन, गंगलूर एरिया कमेटी के एसीएम 24 वर्षीय कमलेश नीलकांत भी शामिल थे

रविवार को जीपी सिंह ने सुकमा में दो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस-टेकलगुडेम और सिलगेर का निरीक्षण किया। दोनों पूर्व नक्सली गढ़ों में स्थापित थे। अधिकारियों ने उन्हें ड्रोन, रेडियो डिवाइस और अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित बरामद उपकरण दिखाते हुए वर्तमान स्थिति, नक्सली समूहों की कार्यप्रणाली और जमीन पर बलों द्वारा अपनाई गई नक्सल विरोधी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि बीजापुर जिला हाल ही में बड़े नक्सल ऑपरेशन को लेकर सुर्खियों में है।पिछले एक साल से बीजापुर में कई इनामी नक्सली ढेर हुए हैं।जिसमें सीआरपीएफ का बड़ा योगदान है। पुलिस डेटा के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से अब तक मारे गए 55 नक्सलियों में से 25 अकेले बीजापुर जिले में ढेर हुए हैं।

वर्तमान में लगभग 40000 सीआरपीएफ जवान पूरे छत्तीसगढ़ में तैनात हैं, जो राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि लगभग 600 नक्सली अब भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में मौजूद हैं। 31 मार्च 2026 तक नक्सली हिंसा को खत्म करने की सरकार की डेडलाइन के बाद सुरक्षा अभियान तेज हो गए हैं। 2024 में बलों ने 250 नक्सलियों का सफाया किया जबकि 812 को गिरफ्तार किया। 723 ने आत्मसमर्पण किया।

### उपमुख्यमंत्री ने किया रोड शो, बोले-

# नेता प्रतिपक्ष का चांपा नगर में नहीं चलेगा जादू : विजय शर्मा

**जांजगीर चांपा।** जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर पालिका चुनाव में 27 वार्डो के भाजपा पार्षद प्रत्याशी और अध्यक्ष पद प्रत्याशी के समर्थन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया रोड शो। सैकडों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा इस बार चांपा में भाजपा की सरकार बनेगी, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का नहीं चलेगा कोई जादू मंतर जनता इस बार भाजपा को भरी मतों से जीता रही है।

चांपा नगर पालिका में कांग्रेस की 10 वर्षो से सरकार थी जिसपर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जन सैलाब से साफ पता चल रहा है सैकड़ों की संख्या में भीड़ रैली में शामिल है चांपा के नगर पालिका में भाजपा की सरकार बना रही है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रोड शो के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है इस नगरीय निकायों की चुनाव ने अपना वोट बीजेपी को को दे तीसरी इंजन की सरकार बनाए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने चांपा के नागरिकों के लिए एक संदेश भेजा है भाजपा की सरकार बनने के बाद चांपा शहर में विकास की धारा बहेगी हम तस्वीर बदल देगे। सभी 27 वार्डो के पार्षद प्रत्याशी और अध्यक्ष प्रत्याशी प्रदीप नामदेव को प्रकांड मतों से जीता कर भाजपा की सरकार बनाए।

नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का चांपा में अच्छी पकड़ है जिसपर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इस बार चांपा किसी का जादू मंतर नहीं चलेगा हम अपने और कार्यकर्ता की मेहनत से चुनाव जीत रहे है। यह तो पहले ही फर्क पड़ा हुआ है हमारे अध्यक्ष प्रत्याशी पर आम सहमति बन चुकी है जन सैलाब बता रही है जीत तय है नहीं चलेगी किसी की जादू मंतर।

# जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही नवजात बच्चों की हुई अदला-बदली

**दुर्ग।** जिला अस्पताल दुर्ग में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिससे दो परिवारों में हड़कंप मच गया है। अस्पताल के मेटरनिटी वार्ड में स्टाफ की चूक के कारण दो नवजात शिशु आपस में बदल गए। यह गंभीर मामला डिलीवरी के आठ दिन बाद तब सामने आया, जब एक परिवार को संदेह हुआ और उन्होंने शिशु के जन्म के समय की तस्वीरें जांची। इसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि अस्पताल में स्टॉफ ने भारी लापरवाही बरती है। वहीं इस मामले की जांच के लिए कलेक्टर ने टीम गठित कर दी है।

दरअसल मामला सिंह और कुरैशी परिवार से जुड़ा हुआ है। दोनों परिवारों की महिलाओं ने लगभग एक ही समय पर अस्पताल में शिशु को जन्म दिया था। अस्पताल के स्टाफ ने लापरवाही बरतते हुए नवजात बच्चों को गलत परिवारों को सौंप दिया। शुरुआत में किसी को इस अदला-बदली की भनक नहीं लगी, लेकिन आठ दिन बाद जब कुरैशी परिवार को संदेह हुआ, तब उन्होंने बच्चे की जन्म के समय की तस्वीरों की जांच शुरू की। जन्म के समय की तस्वीरों में बच्चा अलग दिखने पर परिवारों ने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की और डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने दुर्ग सीएमएचओ के माध्यम से जांच समिति गठित कर दी है।

जांच के दौरान पता चला कि अस्पताल के स्टाफ ने गलती से दोनों बच्चों को गलत माता-पिता को सौंप दिया था। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सिंह परिवार ने बच्चे की अदला-बदली से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आठ दिन में ही उन्होंने बच्चे से गहरा भावनात्मक लगाव बना लिया है और अब वे किसी भी कीमत पर बच्चे को वापस नहीं करेंगे। वहीं कुरैशी परिवार अपने असली बच्चे को वापस लेने के लिए अड़ा हुआ है। इस लापरवाही के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब सरकारी अस्पतालों में ऐसी लापरवाही सामने आई हो। नवजात शिशुओं की सही पहचान के लिए कई अस्पतालों में आईडी टैग या पहचान चिह्न का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस मामले में स्टाफ की लापरवाही के चलते यह प्रक्रिया ठीक से लागू नहीं की गई। वहीं बच्चे के मामा अमीर खान ने बताया कि 23 जनवरी को शबाना कुरैशी (पति अल्ताफ कुरैशी) और साधना सिंह ने दोपहर क्रमशः 1:25 बजे और 1:32 बजे बेटों को जन्म दिया। अस्पताल में नवजात शिशुओं की पहचान के लिए जन्म के तुरंत बाद उनके हाथ में मां के नाम का टैग पहनाया जाता है, जिससे किसी तरह की अदला-बदली न हो। इसी प्रक्रिया के तहत दोनों नवजातों की जन्म के बाद अपनी-अपनी माताओं के साथ तस्वीरें भी खींची गई थी। डिस्चार्ज के दौरान बच्चा बदला बदली का शक हुआ तो अस्पताल प्रबंधन से शिकायत की गई। जांच में शिकायत सही पाई गई है। अस्पताल के स्टॉफ की लापरवाही के कारण यह हुआ है।

# धर्मनगरी में भू-माफिया बेलगाम डुबान की जमीन की करा ली रजिस्ट्री

**डोंगरगढ़।** धर्मनगरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आलम यह है कि जिस जमीन को सरकार ने किसानों को लाखों रुपए देकर अधिग्रहित किया था, उसी जमीन पर पहले भूमाफियाओं ने कब्जा जमाया, फिर बेंचने की तैयारी में रजिस्ट्री भी करा ली।

बता दें, डोंगरगढ़ में साल 1970 में डैम निर्माण के दौरान पानी निस्तारी के लिए डुबान क्षेत्र (बड़ा तालाब) में किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया गया था। इसके एवज में किसानों को साल 1988 में लाखों रुपए का मुआवजा भी दिया था। लेकिन राजस्व विभाग ने अब तक अधिग्रहित भूमि को किसान के नाम से सरकारी (डुबान क्षेत्र) के नाम पर स्थानांतरित नहीं किया। प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही का फायदा उठाते हुए भू-माफियाओं ने साल 2022-23 में किसानों से बड़ा तालाब की जमीन को लगभग 1 करोड़ रुपए में खरीद ली और फिर बेंचने के इरादे से रजिस्ट्री भी करा ली है।

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जल संसाधन विभाग ने सरकारी डुबान क्षेत्र का सीमांकन कराया। सीमांकन में यह खुलासा हुआ कि क्षेत्र में रजिस्ट्री कराई गई सभी जमीनें सरकार की है, जिसके बाद यह पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

गांव के पटेल घनश्याम साहू ने बताया कि बड़ा तालाब में कुछ भू माफियाओं ने किसानों को गुमराह कर डुबान जमीन की रजिस्ट्री कराई है। सबको पता है कि यह जमीन सरकारी डुबान भूमि है और 1988 में इस जमीन का मुआवजा भी जल संसाधन विभाग द्वारा किसानों को दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी इन जमीनों की रजिस्ट्री धड़ल्ले से हो रही है।

बता दें, यह पहली बार नहीं है जब डोंगरगढ़ के अछोली क्षेत्र में इस तरह का मामला सामने आया है। इससे पहले भी भू-माफियाओं ने सरकारी जमीन की खरीद-फरोख्त कर प्रशासन को गुमराह किया था। अछोली इलाका भू-माफियाओं का गढ़ बन चुका है। वहीं प्रशासन की लापरवाही इनके मंसूबों को और बल दे रही है।

हाल ही में अछोली में अवैध प्लाटिंग की खबरें सुर्खियों में रही, जिसके बाद प्रशासन ने औपचारिकता निभाते हुए कुछ जमीन के टुकड़ों को प्रतिबंधित किया था। लेकिन कई हिस्सों पर अब भी खरीद-बिक्री जारी है। फिलहाल इस ताजा फर्जीवाड़े पर डोंगरगढ़ स्ङरू मनोज मरकाम ने जांच कर कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

# भाजपा उम्मीदवार पवन अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर

**कोरबा।** कटघोरा भाजपा नेता और पार्षद उम्मीदवार पवन अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गोंडवाना पार्टी के एक सदस्य ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने पवन अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। यह मामला एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। आदिवासी समुदाय की भावनाओं को आहत करने के आरोप में पवन अग्रवाल पर जातिसूचक शब्दों का उपयोग करने का आरोप है।

उन्होंने आदिवासी नेताओं को गोंड-गंवार कहकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो एसडीएम की बैठक के दौरान की गई थी। आदिवासी नेता इस टिप्पणी से नाराज होकर कटघोरा थाने पहुंचे और मामले की कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी ने मामले की पुष्टि की और कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पवन अग्रवाल वार्ड क्रमांक छह से भाजपा प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। पहले भी विवादों में फंसे रह चुके हैं।

गोंडवाना पार्टी के नेता लाल बहादुर कोर्राम की शिकायत पर ही यह कार्रवाई की गई है। आवेदकों के द्वारा सत्ताधारी दल के नेता होने का दबाव बनाने का भी आरोप पवन अग्रवाल पर लगाया गया है। जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल से आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई है।

गोंडवाना पार्टी के नेता लाल बहादुर कोर्राम ने बताया कि एसडीएम सभागार में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नियमों की जानकारी दी जा रही थी। इस दौरान बताए जाने पर पवन अग्रवाल ने कहा कि हमें समझाने की जरूरत नहीं है कि गोंड गंवार नहीं है और आदिवासी भाइयों पर टिप्पणी की गई। इसके बाद सभागार में हंगामा हुआ और विरोध प्रदर्शन किया गया। काफी समय बाद मामला शांत होने के बाद पार्टी ने फैसला लिया कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसकी शिकायत की गई है। जिस पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है।

**छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार**

## कांग्रेस नेता जांगिड़ ने ईवीएम से चुनाव पर उठाया सवाल

**तखतपुर।** एआईसीसी के संयुक्त सचिव और प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी विजय जांगिड़ ने सोमवार को तखतपुर में कांग्रेस पार्षद चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी पूजा कौर मक्कड़ और सभी 15 पार्षदों के लिए जनसमर्थन मांगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार एक ही ईवीएम पर अध्यक्ष और पार्षद के लिए वोट डाले जाएंगे। इस पर जांगिड़ ने सवाल खड़े करते हुए चुनाव में वोट इधर उधर होने की आशंका जताई। आम जनता को संबोधित करते हुए विजय जांगिड़ ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं ईवीएम और बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर मीडिया के सवाल पर सरकार की मंशा पर प्रश्नचिन्ह लगाया। उन्होंने कहा, नगरीय निकाय में ईवीएम और पंचायत में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। पहली बार एक ही ईवीएम पर अध्यक्ष और पार्षद के लिए वोट डलवाए जाएंगे। इसके चलते वोट इधर-उधर होने की आशंका है। जांगिड़ ने कहा, डमी ईवीएम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाएंगे और मतदाताओं को जागरूक करेंगे।

## भानुप्रतापपुर-अंतागढ़ के बीच शुरू हुई इलेक्ट्रिक रेल सेवा

**भानुप्रतापपुर/कांकेर।** भारत में इलेक्ट्रिक रेल सेवा की आज 3 फ़रवरी को 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर भानुप्रतापपुर-अंतागढ़ रेल खंड पर आज इलेक्ट्रिक गुड्स ट्रेन चलाई गई। इसके साथ ही पूरा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) जोन इलेक्ट्रिफाई हो गया है। रायपुर डिवीजन के एडीआरएम बजरंग अग्रवाल ने भानुप्रतापपुर में हरी झंडी दिखाकर विद्युत ट्रेन को अंतागढ़ के लिए रवाना किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में एडीआरएम बजरंग अग्रवाल ने बताया कि आज भारतीय रेल की विद्युतीकरण के 100 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इस अवसर पर दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे विभिन्न आयोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आज भानुप्रतापपुर से अंतागढ़ के बीच विद्युत् रेल सेवा शुरू होने के साथ हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूरा एसईसीआर जोन विद्युतिकृत हो गया है। कार्यक्रम के दौरान रेल विकास निगम और रेल विद्युत् सेवा के अधिकारी भी मौजूद थे।

## परिवहन आयुक्त ने आरटीओ अफसर को हटाया

**राजनांदगांव।** जिले के पाटेकोहरा आरटीओ में ड्राइवर से मारपीट मामले में अपर परिवहन आयुक्त ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने पाटेकोहरा आरटीओ से परिवहन इंस्पेक्टर संतोष झा को हटाकर रायपुर मुख्यालय अटैच कर दिया है। बता दें कि पाटेकोहरा आरटीओ में आरटीओ अधिकारी ने ड्राइवर की पिटाई की थी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हंगामा करते हुए घटना का विरोध किया था। शनिवार की देर शाम चिचोला एनएच- 53 के पाटेकोहरा में पदस्थ आरटीओ अधिकारी और एक ट्रक चालक के बीच अवैध वसूली को लेकर कहा सुनी हुई थी। इस दौरान अफसर ने ड्राइवर की की जमकर पिटाई की थी। इसके बाद आक्रोशित ट्रक चालकों ने चक्काजाम कर जमकर नारेबाजी की थी। इस दौरान लगभग 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया था।

## हाईकोर्ट में संजीवनी 108 वाहनों की बदहाल स्थिति पर सुनवाई

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ में संजीवनी 108 इमरजेंसी सेवा के गाड़ियों की बदहाल स्थिति की खबरों को संज्ञान लेकर जनहित याचिक के रूप में उच्च न्यायालय ने सुनवाई की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने संजीवनी 108 के वाहनों की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई। मामले में विभागीय सचिव से जवाब मांगा गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में 108 वाहनों की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुनवाई में चीफ जस्टिस ने अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर से पूछा कि आपातकालीन स्थिति में अत्याधुनिक तकनीक सुविधा वाली कितनी एम्बुलेंस हैं? इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। वहीं मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी, 2025 को होगी।

## जान का दुश्मन बना चाचा भतीजे पर किया हमला

**रायगढ़।** छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भाई की सरकारी नौकरी लगने पर गाली-गलौज करते हुए धारदार टांगी से अपने ही भतीजे पर वार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत के बाद लैलूंगा पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक, लैलूंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजपुर निवासी हुल्लास पैकरा उम्र 22 साल ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पिता रतन साय पैकरा पीडब्ल्यूडी विभाग में टाइम स्केल के पद पर लेबर के पद पर नियुक्त थे। पीड़ित युवक ने बताया कि मार्च 2024 में उसके पिता के निधन के बाद उसके पिता के स्थान पर उसकी टाइम स्केल मजदूर के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हुई है। पीड़ित युवक ने बताया कि उसका चाचा मोतीराम पैकरा मेरे भाई की नौकरी को तुम पा गए हो कहकर आये दिन लड़ाई झगड़ा करता था। हुल्लास पैकरा ने बताया मोतीराम फिर से विवाद करते हुए कहने लगा कि तुम मेरे भाई की नौकरी फोकट में पा गये। इसके बाद गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने लगा।

# भारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने गरियाबंद जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की घोषणा की

**गरियाबंद।** भारी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने गरियाबंद जिला पंचायत के लिए सदस्य प्रत्याशियों की अधिकृत सूची जारी कर ही दी है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहे संजय नेताम को क्षेत्र क्रमांक 7 से दोबारा मौका दिया गया है।

कांग्रेस में गुटबाजी व कलह के चलते एक धड़ा जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कराने का दांव-पेच कर रहा था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने दबाव को दरकिनार करते हुए संगठन की गरिमा और कायदों के अनुरूप नामांकन भरने के अंतिम समय में अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दिया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी से प्राप्त निर्देशों के आधार पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाव सिंह साहू ने सोमवार को सूची जारी की है, जिसमें क्षेत्र क्रमांक 1 से होमा देवी सांग, क्षेत्र क्रमांक 2 से मालती साहू, क्रमांक 3 से प्रकाश साहू, क्रमांक 4 से पुनारद ठाकुर, क्रमांक 5 से रजनी चौरे, क्रमांक 6 से सुरेखा नागेश, क्रमांक 7 से संजय नेताम, क्रमांक 8 से सरस्वती नेताम, क्रमांक 9 से उमेश डोंगरे, क्रमांक 10 से छाया देवी नेताम और क्रमांक 11 से राजकुमार प्रधान को प्रत्याशी घोषित किया गया है।

### क्षेत्र क्रमांक 7 के दावेदारों की दिल्ली तक रही चर्चा

अधिकृत सूची का पेंच क्रमांक 7 को लेकर फंसा था। इस सीट से पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने अपनी दावेदारी शुरू से ठोक रखी थी। लेकिन राजनीतिक विरोधियों किसी दूसरे के नाम को आगे बढ़ा दिया था। स्थिति यह हो गई कि इस सीट पर अधिकृत नाम को लेकर चर्चा दिल्ली तक पहुंच गई थी। आखिरकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुमोदन के बाद अंततः जिला कांग्रेस कमेटी को अधिकृत सूची जारी करना पड़ा।

# दो सगे भाई लड़ रहे पार्षद चुनाव, एक को भाजपा तो दूसरे को कांग्रेस ने दिया टिकट

### ■ पिता बोले- चुनाव कोई भी जीते, परिवार में खुशी की लहर

**धमतरी।** छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखा जा रहा है। कहीं गुपचुप वाले, चाय वाले तो कहीं सगे भाई आमने-सामने मैदान पर हैं। ऐसा ही मामला धमतरी जिले के कुरुद से आया है, जहां नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-10 में 2 सगे भाई राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े भाई को भाजपा तो छोटे भाई को कांग्रेस से पार्षद का टिकट मिला है।

कुरुद नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 स्वामी विवेकानंद वार्ड में भाजपा ने कमलेश ध्रुव को अपना उम्मीदवार बनाया है।

वहीं कांग्रेस ने अर्जुन ध्रुव को मैदान में उतारा है। बड़ा भाई कमलेश 45 साल और छोटा भाई अर्जुन 33 साल के हैं। दोनों भाई कभी बचपन में एक साथ खेला करते थे। अब चुनावी मैदान में दोनों भाई आमने-सामने हैं। बता दें कि दोनों भाई पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।

कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन ध्रुव का कहना है कि कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास कर प्रत्याशी बनाया है। यह लड़ाई हम दोनों भाइयों के बीच न होकर भाजपा और कांग्रेस के बीच है। बड़े भाई चुनाव जीतते हैं तो भी मुझे खुशी होगी।

वहीं भाजपा प्रत्याशी कमलेश ध्रुव का कहना है कि कांग्रेस ने छोटे भाई अर्जुन ध्रुव को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों भाइयों का प्रचार जारी है। दोनों प्रत्याशियों के पिता लच्छन ध्रुव ने कहा कि दोनों बेटों को पार्षद का टिकट मिला है, इससे परिवार में खुशी है। दोनों में से कोई भी जीते पार्षद तो उनके परिवार से ही बनेंगे।

बता दें कि वार्ड क्रमांक 10 को शुरू से भाजपा का गढ़ माना जाता है। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस से तुमेश्वरी ध्रुव चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गई थी। इस बार वार्ड 10 से दो ही प्रत्याशी होने से चुनावी समीकरण भी स्पष्ट है। दोनों में से एक भाई का जीत तय है।

## संक्षिप्त समाचार

### भाजपा महापौर प्रत्याशी के ठेले में मंत्री ओपी चौधरी ने बनाई चाय

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में चारों तरफ नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का शोर है। इसी बीच सोमवार को रायगढ़ नगर निगम के भाजपा महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान से उनके चाय ठेले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मुलाकात की। उन्होंने चाय भी बनाई। मंत्री चौधरी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर लिखा है कि आज रायगढ़ नगर निगम के भाजपा महापौर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान से उनके चाय ठेले में मुलाकात की और चाय भी बनाई, जिसका हम सभी ने आनंद लिया। यह लोकतंत्र की असली पहचान है, जिसमें एक साधारण चाय वाला भी महापौर बन सकता है।

### फर्जी प्रमाण पत्र पेश करने पर दिनेश इंजीनियरिंग के खिलाफ एफआईआर

**रायपुर।** छत्तीसगढ में बीएसएनएल की ओर से जारी की गयी निविदा में भाग लेने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मेसर्स दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड के विरूद्ध चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराये हैं। चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, मेसर्स दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में जाँच करने पर यह संज्ञान में आया कि ऐसा अनुभव प्रमाण पत्र चिप्स में दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड को कभी जारी ही नहीं किया गया था। चिप्स ने पत्राचार के माध्यम से में. दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड से यह जानने का हर संभव प्रयास किया कि यह अनुभव प्रमाण पत्र उन्हें (मे. दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड) कैसे और किसकी मदद से प्राप्त हुई। हालांकि दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड ने अब तक अपेक्षित जानकारी नहीं दी है। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए इस घटना की पूर्णत: निष्पक्ष और व्यापक जाँच के लिये सीईओ चिप्स ने 2 फरवरी 2025 मे. दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड के विरुद्ध सिविल लाइन्स थाने में आवश्यक कार्यवाही करने के आवेदन दिया गया है। बीएसएनएल द्वारा जारी की गयी निविदा में भाग लेने हेतु मे. दिनेश इंजीनियरिंग लिमिटेड ने चिप्स के भारतनेट फेज-2 परियोजना के अनुभव प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेज़ में इस्तेमाल किया है।

### व्यावसायिक शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन महीनों से वेतन नहीं मिलने से हैं परेशान

**रायपुर।** प्रदेश भर के व्यावसायिक शिक्षक पिछले चार महीनों से वेतन न मिलने की वजह से परेशान हैं और उन्हें समग्र शिक्षा कार्यालय के बाहर अपनी परेशानियां जताने के लिए मजबूर हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि उन्हें उनकी मेहनत का उचित मेहनताना समय पर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उनका जीवन मुश्किल हो गया है। शिक्षक संगठन ने अपग्रेड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड और ग्राम तरंग कम्पनी को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। शिक्षकों का आरोप है कि इन कंपनियों ने उन्हें वेतन देने में जानबूझकर देरी की है, जबकि ठेकेदारों को भुगतान कर दिया गया है। बता दें, समग्र शिक्षा और इन कंपनियों के बीच हुए अनुबंध का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे व्यावसायिक शिक्षकों की समस्याएं और बढ़ रही हैं। शिक्षक संघों ने सवाल उठाया है कि इन ठेकेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, जो एमओयू का पालन नहीं कर रहे हैं और शिक्षकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। संगठन ने प्रदेश सरकार से जल्द समाधान की मांग की है, ताकि वेतन भुगतान में देरी को रोकने और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

### नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत का सनसनीखेज बयान

**कोरबा।** नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनज कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर कोई कोयला, कबाड़, डीजल और रेत तस्कर आरोप लगाए कि कांग्रेस के किसी मंत्री, सांसद को पैसे देते हैं, तो उसे सरेआम पांच चप्पल मारना। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान डॉ। चरण दास महंत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोयला, डीजल, कबाड़ और रेत तस्करी के मामले में सबसे आगे है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास ने कहा कि कोयला, डीजल, कबाड़ और रेत तस्कर हमारे सिर पर नाच रहे हैं। जो भी इस अवैध काम मे लगे हैं, जुड़े हैं, तो उनको खुला चैलेंज है कि सुधर जाए या कांग्रेस को जिताये। नहीं तो उन्हें एक साल बाद भगाया जाएगा। जनता से जाकर पूछना कि मंत्री को कितना कमीशन मिलता है।

### कांग्रेस नेता पर निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने का आरोप

**बिलासपुर।** छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के प्रचार में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बिलासपुर के कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास के पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायत जिला कांग्रेस कमेटी और पीसीसी चीफ से की गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज से निष्कासन की मांग की है। वहीं सह प्रभारी विजय जांगड़े ने कार्रवाई की जाने की बात कही है। दरअसल, बिलासपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 68 से कांग्रेस ने प्रीति मनीष गढ़ेवाल को टिकट दिया है। प्रीति ने शिकायत पत्र में बताया कि वार्ड नंबर 68 रामकृष्ण परमहंश कोनी से कांग्रेस नेता त्रिलोक श्रीवास द्वारा अपने भाई की पत्नी योगिता श्रीवास को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतार कर पार्टी विरोधी कार्य किया जा रहा है। जिससे कांग्रेस और पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी को नुकसान पहुंच रहा है। प्रीति गढ़ेवाल ने पीसीसी चीफ से निष्कासन की कार्रवाई की मांग की है।

# नगरीय निकाय चुनाव : भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे अटल विश्वास पत्र का नाम दिया गया है। भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में घोषणा पत्र जारी किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी सहित घोषणा पत्र समिति के सदस्य मौजूद रहे।

भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र 'अटल विश्वास पत्र' जारी कर दिया है। यह घोषणापत्र अटल जी की 100 वीं जयंती और 'अटल निर्माण वर्ष' के अवसर पर उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण को सम्मानित करते हुए समर्पित किया गया है। घोषणापत्र को तैयार करने के लिए हमने प्रदेशव्यापी 'सुझाव संग्रहण अभियान' चलाया, जिसमें जनता से उनके सुझाव और अपेक्षाएं मांगी गईं। हमें हज़ारो सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से महत्वपूर्ण सुझावों को हमारी घोषणापत्र समिति ने शामिल किया। यह घोषणापत्र जनता की आकांक्षाओं और हमारी पार्टी के सेवा भाव का प्रतीक है।

### जानिए घोषणा पत्र में क्या है खास

हम नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे और सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाएंगे। रुकी हुई पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करेंगे और वर्तमान में स्वीकृत 3 लाख पीएमएवाई-यू घरों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, जो लोग बिजली बिल और समेकित कर चुकाते है, उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी।

**नगरीय सेवाओं में सुधार-** हम सिकल सेल एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीज़ों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे। नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए 'माई सिटी ऐप' लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सभी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, हम 'सरकार तुंहर द्वार' योजना के तहत शासकीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। हर ज़ोन में एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को बार-बार नगर निगम कार्यालय न जाना पड़े। निदान हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। संपत्ति कर समय पर चुकाने वाले नागरिकों को 10त्न की विशेष छूट और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर 25% विशेष छूट दी जाएगी।

**जल आपूर्ति और स्वच्छता-**हम शुद्ध पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 'नल से जल' योजना को सुदृढ़ करेंगे, नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे। शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक घर में कचरा बाल्टी प्रदान की जाएगी और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग की जाएगी। तालाबों की सफाई और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एस ।टी ।पी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जोड़ा जाएगा।

**महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं-** महिलाओं और छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, हम विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे वे साफ और सुरक्षित सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त, महतारी वंदन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह लाभार्थियों को 2.5 लाख रूपए तक का ऋ्रण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।

**रोजगार और शिक्षा का विस्तार-** हम प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में सीटों की संख्या भी बढ़ाएंगे। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम राज्यभर में रोजगार मूलक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स स्थापित करेंगे, जो युवाओं के लिए उद्यमशीलता, व्यक्तित्व विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे। यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रू. की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रत्येक नगर निगम में 'महापौर सम्मान निधि' की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, हम विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे, जिससे छात्र डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठा सकें। यह कदम केंद्र सरकार के हालिया बजट में घोषित स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लक्ष्य के अनुरूप रहेगा।

**स्ट्रीट वेंडर्स और व्यापारिक केंद्रों का विकास-** हम स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत ?30,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन और फूड स्ट्रीट्स की स्थापना करेंगे तथा सड़क व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक समुचित नीति बनाएंगे। प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

**न्यायसंगत कर प्रणाली-** हम उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) से जुड़ी समस्याओं का वाजिब समाधान करेंगे। समाधान योजना के माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान की सुविधा देंगे। यह घोषणा-पत्र न केवल नागरिकों को बेहतर जीवन का वादा करता है, बल्कि उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठाने की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है।

**हर चुनाव, सेवा का एक अवसर-** बीजेपी के लिए हर चुनाव जनता की सेवा का एक अवसर है। हम सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं और जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को हल करना हमारी प्राथमिकता है। हमारी पार्टी जनता-केंद्रित है, जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। यही सच्चे लोकतंत्र का आधार है। इसके विपरीत, अन्य पार्टियां—जैसे कांग्रेस—दिल्ली में बैठे परिवार या राजस्थान से आए नेताओं के इशारों पर चलती हैं।

**कांग्रेस का कुशासन और भ्रष्टाचार-** कांग्रेस का इतिहास छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और कुशासन का रहा है। जब भी उन्हें सत्ता मिली, उन्होंने राज्य को लूटने और जनता के पैसों का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के लिए नगर पालिकाएं केवल एक 'वसूली तंत्र बनकर रह गई थीं, जिसका उद्देश्य केवल जनता से पैसे वसूलना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था। इन निकायों का उपयोग कांग्रेस ने नई निर्वाचित बीजेपी राज्य सरकार की योजनाओं को बाधित करने और जनता के पैसों का दुरुपयोग अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए 'एटीएम' की तरह किया।

कांग्रेस की यह वसूली तंत्र, निकाय स्तर पर बीजेपी-शासित राज्य सरकार की योजनाओं को कमजोर करने और जनता तक लाभ पहुंचने से रोकने का हर संभव प्रयास करती रही। इसके बावजूद हमने हर बाधा को पार करते हुए अपने वादों को पूरा करने की कोशिश की। जनता अब कांग्रेस के इस कुशासन और भ्रष्टाचार को भली-भांति समझ चुकी है और इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है।

**जनता का विश्वास, हमारा विजन-** इस बार जनता हमारे विजन को देखेगी और कांग्रेस को हर स्तर पर सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेगी। हमने हर वादा पूरा करने का प्रयास किया है, और अब जनता का साथ लेकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार को छत्तीसगढ़ से पूरी तरह खत्म करेंगे। अटल जी ने कहा था, मैं यहाँ वादे लेकर नहीं, इरादे लेकर आया हूँ और हमारे इरादे ही हमें जनता की सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि बीजेपी का यह घोषणापत्र जनता के सुझावों और जरूरतों पर आधारित है—यह केवल एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सेवा में बनाया गया रोडमैप है। कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति का यह समय है, और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता का फैसला स्पष्ट होगा। जैसा कि मोदी जी ने कहा था, भाजपा की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी हम अपनी गारंटी को पूरी तरह निभाकर जनता के विश्वास को और मजबूत करेंगे।

**भाजपा घोषणा पत्र पर पीसीसी चीफ का तंज**

# पहले पुराने वादे पूरे कर लें, फिर नए पर जाएं

**रायपुर।** बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर अरुण साव के बयान कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए कहा कि पहले बताएं कि अभी तक कितने वादे किए हैं, और कितने पूरे किए हैं? पहले अपने पुराने वादे पूरे कर लें, फिर नए वादों पर जाएं। यह भी पढ़ें = राजेश अवस्थी के निधन से शोक में भाजपा, बदला नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करने का समय

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा में बागी होकर चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि अधिकृत प्रत्याशी होने के बावजूद नाम वापस लेने वालों पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रचार में तेजी आने की बात कहते हुए कहा कि शानदार जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। एक साल में सरकार ने कुछ काम नहीं किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय प्रचार के प्रचार अभियान की कमान संभालने पर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नगरी निकाय क्षेत्रों में क्या किया, यह जनता को बताएं। एक साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया। जनता के बीच झूठे वादे करके आएंगे।

# बसंत पंचमी पर्व पर मुख्यमंत्री साय पहुंचे मां शारदा धाम

- **सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की**

**रायपुर।** विद्यादायनी माता सरस्वती की उपासना के पावन पर्व बसंत पंचमी पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जशपुर जिले के दुलदुला तहसील के ग्राम पंचायत जामटोली अंतर्गत ग्राम डेवाडेलंगी में मां शारदा धाम पहुंचे। उन्होंने इस धाम परिसर में स्थित मां सरस्वती मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर शारदा धाम में आए समस्त श्रद्धालुगण को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मां सरस्वती की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। आपके कंठ में सदा मां सरस्वती विराजमान रहें। उन्होंने कहा कि वेदों में कहा गया है कि मानव योनि में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें मानव जीवन मिलता है। हमारे कर्म ऐसे रहने चाहिए कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग हमें याद रखें। इस धाम में शिक्षा के लिए अलख जगाने के साथ ही खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय मां शारदा के पावन धाम में आयोजित अखण्ड श्रीहरि कीर्तन राम नाम जाप के आयोजन में भी शामिल हुए, जिसमें आसपास के 48 गांवों के श्रद्धालु और 12 कीर्तन मंडलियां शामिल हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल के निकट गिरमा नदी बहती है, जिसके एक ओर छत्तीसगढ़ है तो दूसरी ओर झारखंड है। इस धाम के बगल में बह रही पावन गिरमा नदी दो प्रदेशों की संस्कृति को समाहित कर अविरल धारा के साथ बह रही है।

### हर्षोल्लास व भक्तिभाव के साथ मनाया गया बसंतपंचमी पर्व

बसंत पंचमी का पर्व जैतूसाव मठ व दूधाधारी मठ में हर्षोल्लास व भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्या की देवी माता सरस्वती,शिवम भगवान राघवेंद्र सरकार राधा कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई आम का मौर गेहूं की बाली तथा पुष्प गुलाल चंदन धूप नावेद अर्पित किया गया .पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया।

राजेश्री महंत रामसुंदर दास ने कहा बसंत उत्सव सनातन धर्मावलंबियों का एक प्रमुख त्यौहार है इस दिन विद्या दयानी माता सरस्वती की पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है जो भी श्रद्धालु भक्ति विधिवत पूजा अर्चना करता है उन्हें बल बुद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अजय तिवारी ने कहां की जैतूसाव मठ में प्रत्येक वर्ष मांघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। सभी भक्तजन पूजा अर्चना में शामिल हुए श्री महेंद्र अग्रवाल, रामअवतार तिवारी, दीपेंद्र सोनी, रमेश यदु, चंद्रकांत यदु, हर्ष दुबे, सुमित तिवारी, गोविंद दास दीपक दास, निर्मल दास वैष्णव, शारदा शुक्ला, शैल अग्रवाल, शालिनी, संतोषी, मोहिनी अग्रवाल, मनीषा, योगिता यादव के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

# किसानों को अब सहमति से जमीन देने पर मिलेगा चार गुना मुआवजा

**रायपुर।** नवा रायपुर अटल नगर परियोजना के अंतर्गत प्रभावित किसानों व भूमि-स्वामियों को अब कलेक्टर गाइडलाइन दर से चार गुना मुआवजा मिलेगा। पहले नवा रायपुर के प्रभावित किसानों को उनकी जमीन का केवल दोगुना मुआवजा मिलता था। इसके लिए नया रायपुर राज्य सरकार ने अटल नगर विकास प्राधिकरण की 'नया रायपुर में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2017' में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक राज्य शासन के निर्णय के बाद नवा रायपुर अटल नगर परियोजना क्षेत्र में आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली जमीन का मुआवजा चार गुना प्रदान किए जाने से प्रभावित किसानों को काफी फायदा होगा। वहीं, जिन किसानों ने परियोजना क्षेत्र में आपसी सहमति से अपनी जमीन प्राधिकरण को नहीं दी है, वे अब अपनी जमीन आपसी सहमति से प्राधिकरण को अधिक कीमत पर बेच सकेंगे। बताया गया है कि नवा रायपुर अटल नगर परियोजना क्षेत्र में कुछ सड़क सहित अन्य निर्माण कार्य जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अधूरे पड़े हुए हैं।

नवा रायपुर अटल नगर परियोजना क्षेत्र में 41 गांवों को शामिल किया गया है। शासन द्वारा नवा रायपुर अटल नगर लेयर-1 के अंतर्गत आने वाले गांवों में किसानों की ज्यादातर जमीनें आपसी सहमति या अधिग्रहण के माध्यम से ली जा चुकी हैं। इनमें कुछ किसानों की जमीनें आपसी सहमति से लेना बाकी है, जिन्हें अब चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा लेयर-2 व लेयर-3 के अंतर्गत आने वाले गांवों के प्रभावित किसानों को भी इसी नीति के तहत जमीन का मुआवजा मिलेगा।

नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर का कहना है कि नवा रायपुर के प्रभावित किसानों को आपसी सहमति से भूमि क्रय करने पर 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय स्वागत योग्य है। राज्य शासन वास्तव में किसानों की हितैषी है तो नवा रायपुर से लगे क्षेत्रों में जमीन की जो कीमत है, उसका चार गुना मुआवजा मिले, तो किसानों को फायदा होगा। साथ ही प्रभावित किसानों के लिए पुनर्वास नीति भी बनाई जानी चाहिए।

# रायपुर क्षेत्र के बिजली कर्मियों को पुरस्कार

**रायपुर ।** छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमि., गुढ़ियारी रायपुर क्षेत्रीय मुख्यालय में ''गणतंत्र दिवस'' के अवसर पर मुख्य अभियंता श्री एम.जामुलकर ने रायपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। चयनित कर्मियों कार्या.सहायक श्रेणी-दो श्रीमती कीर्ति शुक्ला, कार्या.सहायक श्रेणी-एक श्री परसराम कृश्णानी, कार्यपालन अभियंता श्री ताराचंद साहू, कार्या.सहायक श्रेणी-दो श्री राकेष कुमार वर्मा, परि.श्रेणी-दो(ला.) श्री प्रदीप कुमार यादव, परीक्षण सहायक श्रेणी-एक श्री योगेश्वर एवं रायपुर ग्रामीण क्षेत्र से सर्वश्री सहायक अभियंता नंदकिशोर चैधरी, कार्या. सहायक श्रेणी-एक श्री प्रहलाद कुमार साहू, लाईन परिचारक (संविदा) श्री जागेन्द्र कुमार नेताम , परि.श्रेणी-एक(ला.) श्री मनोज कुमार देवांगन, परीक्षण सहायक श्रेणी-एक श्री मनोज कुमार धृतलहरे, परि.श्रेणी-एक(ला.) श्री खेमलाल साहू को विद्युत कम्पनी की ओर से देय पदक और प्रशस्ति-पत्र एवं प्रोत्साहन राषि प्रदान कर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। लेखा प्रषिक्षण का.स.श्रे.-दो श्री लक्ष्मीकांत साहू एवं तकनीकी प्रषिक्षण में परिचारक लाइन श्री अमन दुबे को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया।

श्री जामुलकर ने कहा कि विद्युत विकास में अहम भूमिका निभाने वाले विद्युतकर्मी श्रेष्ठ और सम्माननीय है।राज्य के विकास में हमारी अहम सहभागिता दर्ज है ,इस कार्य को करने के पीछे टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्हें चिन्हित कर उचित सम्मान प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर उन्होंने पुरस्कृत सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी।

# 10,00,00,00,000 की गड़बड़ियों के सबूत मिले

**रायपुर।** राइस मिलर्स, एक्सपोर्ट्स कमीशन एजेंट्स, राइस ब्रोकर्स के ठिकानों पर की गई आयकर छापे की कार्रवाई में करीब 10,00,00,00,000 रुपए की गड़बड़ियों के दस्तावेज मिले हैं। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश के 25 कारोबारी-आवासीय परिसर में जांच कर आयकर अन्वेषण की सभी टीमें शनिवार देर रात लौट गई। आयकर अन्वेषण की टीमों ने कैश, ज्वेलरी के साथ-साथ गड़बड़ियों के ढेरों दस्तावेज भी सीज कर लिए है।

आयकर अन्वेषण की टीम शनिवार देर रात छापे की कार्रवाई पूरी कर मुख्यालय लौट गई है। शनिवार शाम को राजधानी के एक दफ्तर और एक आवासीय परिसर में टीम ने सत्यम बालाजी समूह के संचालकों का बयान दर्ज कर छापे की कारवाई पूरी कर ली है। सभी ठिकानों की जांच में कैश में कामकाज किए जाने के साथ-साथ बुक्स के रिकार्डस में भी अनियमितताएं मिली है। इसके साथ ही कच्चे में लेनदेन किए जाने के भी पेपर्स मिले हैं। आयकर अन्वेषण की छत्तीसगढ़ की सभी टीमों ने लौटकर जब्त दस्तावेज मुख्यालय में जमा कर दिया है। अब अगले चरण में राइस मिल संचालकों और कमीशन एजेंट्स व राइस ब्रोकर्स से मिले दस्तावेज की वाहन जांच कर अप्रेजल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ज्ञात रहे कि बीते सप्ताह बुधवार को राजधानी रायपुर के साथ ही राजिम, धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग, तिल्दा के साथ ही गोंदिया (महाराष्ट्र) और काकीनाड़ा (आंध्रप्रदेश) मिलाकर 25 ठिकानों पर आयकर छापे की कार्रवाई की थी। इस अभियान में आयकर अन्वेषण छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश के करीब सौ अफसर शामिल थे।

# 'रेवड़ियों' पर सिमटी दिल्ली में चुनावी चाल

**राज कुमार सिंह**

मतदाताओं का मन तो आठ फरवरी को पता चलेगा, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरी तरह मुफ्त रेवड़ियों के वायदों पर लड़ा जा रहा है। दस साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज 'आप' इस बार भी मुफ्त रेवड़ियों के सहारे मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो रेवड़ी-राजनीति को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बतानेवाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा भी रेवड़ियां बांटने की स्पर्धा में किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। कभी लगातार 15 साल दिल्ली में सत्तारूढ़ रही, पर पिछले दो विधानसभा चुनावों में खाता तक खोलने में नाकाम कांग्रेस की भी सारी उम्मीदें मुफ्त रेवड़ियों के वायदों पर टिकी हैं। चुनाव घोषणापत्रों के नये नामकरण के इस दौर में भाजपा दिल्ली चुनाव के लिए अभी तक तीन हिस्सों में अपना 'संकल्प पत्र' जारी कर चुकी है। पानी, बिजली, महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा तथा बेहतर शिक्षा-स्वास्थ्य से अपनी अलग पहचान बनानेवाली आप ने अभी तक लागू न हो पायी महिला सम्मान योजना की राशि 1,000 रुपये से बढ़ा कर 2,100 करने का ऐलान किया, तो कांग्रेस और भाजपा ने 2,500 रुपये का वायदा कर दिया। 'आप' ने पुजारियों और ग्रंथियों के वेतन का ऐलान किया, तो कांग्रेस ने दिल्ली में बड़ा वोट बैंक बन चुके पूर्वांचलियों के लिए विकास बोर्ड बनाने का वायदा कर दिया है। कांग्रेस युवाओं को एक साल की इंटर्नशिप और साढ़े आठ हजार रुपये मासिक देने का वायदा कर रही है, तो भाजपा ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठनेवाले छात्रों को 15 हजार रुपये देने की बात कही है। कांग्रेस की तरह भाजपा भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर तो देगी ही, होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर भी दिया जायेगा। मुफ्त रेवड़ियों की यह फेहरिस्त लंबी है, पर विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था में भी ऐसी विडंबना पर शर्म किसी के चेहरे पर नजर नहीं आती। पांच साल तक सत्ता में रही भाजपा और 15 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में होने के तर्क के सहारे अपनी वायदों की राजनीति का बचाव करती हैं, तो 10 साल से सत्तारूढ़ आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी यमुना सफाई जैसे अधूरे वायदों के बचाव में पहले ढाई साल 'कोरोना' और फिर 'जेल का खेल' का तर्क देते हुए 15 गारंटियां बांट दी हैं। मुफ्त रेवड़ियों का यह चुनावी खेल तब परवान चढ़ रहा है, जब प्रधानमंत्री के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और नीति आयोग भी मुफ्त रेवड़ियों की राजनीति के आर्थिक खतरों पर चिंता जता चुके हैं। रेवड़ी राजनीति के चुनावी असर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिन-रात केजरीवाल को कोसने वाली भाजपा को कहना पड़ रहा है कि अगर वह सत्ता में आयी, तो भी आप सरकार की जन कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी, पर यह बताने की जहमत कोई दल नहीं उठा रहा कि जन कल्याण के नाम पर बांटी जा रही रेवड़ियों पर कितना खर्च आयेगा और वह कहां से जुटाया जायेगा? सत्ता के तीनों दावेदार खुद अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं। संकल्प पत्र का पहला भाग जारी करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि 500 में से 499 चुनावी वायदे पूरे करने के साथ ही उनकी पार्टी का रिकॉर्ड सबसे बेहतर है। कांग्रेस और आप लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में भाजपा के अधूरे चुनावी वायदे गिना रही हैं। भाजपा भी पंजाब में आप तथा हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी वायदों को अधूरा बता रही है। इन आरोप-प्रत्यारोपों का सच जो भी हो, इतना तय है कि भारत की राजधानी में इस बार भी चुनाव मुफ्त रेवड़ियों के वायदों पर ही लड़ा जा रहा है। महंगाई पर अंकुश और रोजगार बढ़ाने का विजन किसी राजनीतिक दल ने पेश नहीं किया है। ऐसे में, दिल्ली के मतदाताओं को मुफ्त रेवड़ियों के वायदों के आधार पर ही अपनी पसंद का राजनीतिक दल और उम्मीदवार चुनना होगा। हाल ही में आयी भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि खासकर आधी आबादी के वोट बटोरने के लिए की घोषित की जा रही मुफ्त योजनाएं राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां बन रही हैं। दिल्ली में 1,000 रुपये मासिक महिला सम्मान योजना पर ही बजट का तीन प्रतिशत खर्च होने का अनुमान था।

# वित्तीय वर्ष का अग्रणी, पथप्रदर्शक एवं अतुलनीय बजट

**प्रह्लाद सबनानी**

दिनांक 1 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लोकसभा में बजट पेश किया। सीतारमन ने एक महिला वित्तमंत्री के रूप में लगातार 8वां बजट लोकसभा में पेश कर एक रिकार्ड बनाया है। वित्तमंत्री द्वारा लोक सभा में पेश किया गया बजट अपने आप में पथप्रदर्शक, अग्रणी एवं अतुलनीय बजट कहा जा रहा है क्योंकि इस बजट के माध्यम से किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीब वर्ग एवं मध्यम वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। पिछले कुछ समय से देश की अर्थव्यवस्था में विकास की गति कुछ धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी अत: विशेष रूप से मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग के हाथों में अधिक धनराशि शेष बच सके ताकि वे विभिन्न उत्पादों को खरीदकर अर्थव्यवस्था में इनकी मांग बढ़ा सकें, ऐसा प्रयास इस बजट के माध्यम से किया गया है। साथ ही, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से रोजगार उन्मुख क्षेत्रों यथा कृषि क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, निवेश, निर्यात एवं समावेशी विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि इन्हें विकास के इंजिन के रूप में विकसित किया जा सके।

भारत में मध्यमवर्गीय परिवार देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता आया हैं। हाल ही के समय में प्रत्यक्ष कर संग्रहण में व्यक्तिगत आयकर की भागीदारी कारपोरेट क्षेत्र से आयकर की भागीदारी से भी अधिक हो गई है। अत: मोदी सरकार से अब यह अपेक्षा की जा रही थी कि मध्यमवर्गीय परिवारों को बजट के माध्यम से कुछ राहत दी जाय। और फिर, मुद्रा स्फीति की सबसे अधिक मार भी गरीब वर्ग के परिवारों एवं मध्यमवर्गीय परिवारों पर ही पड़ती दिखाई देती है। केंद्रीय वित्तमंत्री ने मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आयकर की वर्तमान सीमा को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। अर्थात अब 12 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने वाले नागरिकों पर किसी भी प्रकार का आयकर नहीं लगेगा। वेतन एवं पेंशन पाने वाले नागरिकों को 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड कटौती की राहत इसके अतिरिक्त प्राप्त होगी। इस वर्ग के करदाताओं को 12.75 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं चुकाना होगा। इसके साथ ही, आय कर की दरों में भी परिवर्तन किया गया है। अब 4 लाख रुपए तक की करयोग्य आय पर आयकर की दर शून्य रहेगी। 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की करयोग्य आय पर आयकर की दर 5 प्रतिशत, 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 10 प्रतिशत, 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 15 प्रतिशत, 16 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर की दर 20 प्रतिशत, 20 लाख रुपए से 24 लाख रुपए तक की कर योग्य आय पर आयकर 25 प्रतिशत एवं 24 लाख रुपए से अधिक की कर योग्य आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा।

मध्यमवर्गीय करदाताओं को उक्त सुधारों से लगभग 80,000 रुपए से 1.10 लाख रुपए तक की राशि की बचत होने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इस सुधार से कुल मिलाकर देश के बजट में एक लाख करोड़ रुपए की राशि कम प्राप्त होगी अर्थात मध्यमवर्गीय परिवारों को कुल एक लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का लाभ होगा। और, यह लाभ लगभग 2 करोड़ करदाताओं को होने की सम्भावना है। इससे देश के मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों के हाथों अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी जिसे वे विभिन्न उत्पादों की खरीद पर खर्च करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सहायक होंगे। मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों ने जितना सोचा था शायद उससे भी कहीं अधिक राहत उन्हें इस बजट के मध्यम से दी गई है। इसीलिए ही, इस बजट को अग्रणी, पथप्रदर्शक एवं अतुलनीय बजट की संज्ञा दी जा रही है।

मध्यमवर्गीय एवं गरीब परिवारों को, आयकर में छूट देकर, दी गई राहत देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि इससे बजटीय घाटा में वृद्धि नहीं हो। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजटीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9 प्रतिशत रहने की सम्भावना पूर्व में की गई थी, परंतु अब संशोधित अनुमान के अनुसार यह बजटीय घाटा कम होकर 5.8 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय घाटा 5.4 रहने का अनुमान लगाया गया है। अत: देश की वित्तीय व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है। हां, पूंजीगत खर्चों में जरूर कुछ कमी रही है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.11 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च के अनुमान के विरुद्ध 10.18 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11.12 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च की व्यवस्था बजट में की गई है। इस राशि को 11.11 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15 लाख करोड़ रुपए किया जाना चाहिए था क्योंकि पूंजीगत खर्च में वृद्धि से देश में आर्थिक विकास की दर तेज होती है और रोजगार के नए अवसर निर्मित होते हैं। इस संदर्भ में एक रास्ता यह निकाला गया है कि केंद्र सरकार के उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियों से अपेक्षा की गई है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये संस्थान भी अपने पूंजीगत खर्चों में वृद्धि करें ताकि उनके द्वारा किए गए पूंजीगत खर्चों की राशि को मिलाकर कुल पूंजीगत खर्च को 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ले जाया जाए।

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि धन धान्य योजना को 100 जिलों में प्रारम्भ किया जा रहा है, इस योजना के माध्यम से इन जिलों में ली जा रही फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दलहन के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए 6 वर्षीय मिशन चलाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 5 लाख तक बढ़ाया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए एवं स्टार्टअप के लिए ऋण की सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जा रहा है। लेदर उद्योग में रोजगार के 22 लाख नए अवसर निर्मित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत को खिलौना उत्पादन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा।

यूरिया उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाया जाएगा। आज भारत खाद्य तेलों का भारी मात्रा में आयात करता है अत: तलहन के क्षेत्र में भी आत्म निर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।। भारत में निर्मित विभिन्न उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजारों की तलाश करते हुए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते सम्पन्न किए जा रहे हैं। देश में बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जा रही है। विभिन्न शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाया जा रहा है।

युवाओं में कौशल विकास के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, आगामी 5 वर्षों में देश के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 युवाओं को अतिरिक्त दाखिला दिए जाएंगे। इंडियन इन्स्टिटूट आफ टेक्नॉलजी कॉलेजों में टेक्नलाजिकल रीसर्च के लिए 10,000 पी एम स्कालर्शिप प्रदान की जाएंगी एवं नए आईआईटी केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। आरटीफिशियल इंटेलीजेंस सेंटर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

श्री अयोध्या धाम, महाकुम्भ क्षेत्र प्रयागराज, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, महाकाल मंदिर उज्जैन की तर्ज पर अन्य धार्मिक स्थलों को भी विकसित किया जाएगा ताकि देश में धार्मिक पर्यटन की गतिविधियों को और अधिक आगे बढ़ाया जा सके। देश में 52 नए पर्यटन केंद्र भी विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है तथा भगवान बुध सर्किट भी विकसित किया जाएगा।

## पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

# वेदों में अष्टादश पुराणों के नाम

**( गतांक से आगे... )**

समानं वृक्ष परिषस्वजाते। तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्वत्त्य, नश्नन्नन्य अभिचाकशीति।। (265) (ऋग्वेद 1 । 164 । 20)

(ख) ते ह प्राणा: प्रजापति पितरमेत्योचुर्भगवन् ! को न: श्रेष्ठ इति? तान् होवाच, यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते सव: श्रेष्ठ इति ।(छान्दोग्य 5 ।1 ।7)

अर्थात् (क) एक साथ रहने वाले परस्पर संयुक्त और सुन्दर पंखों वाले दो पक्षी है, जो दोनों एक वृक्ष का आश्रय लेते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के पिप्पल- फल खाता है। दूसरा बिना खाये ही प्रकाशमान होता है। (ख) प्राणों ने अपने बाप प्रजापति के पास जाकर पूछा कि हम सब (इन्द्रिय मन: प्राण आदि) में बड़ा कौन है ? प्रजापति ने कहा तुम सब में से जिसके निकल जाने पर शरीर पापिष्ठ सा (व्यर्थप्राय:) दीख पड़े, वही तुम में सर्वश्रेष्ठ है ।

यहाँ पहले उदाहरण में जीव और ब्रह्म का दो पक्षियों के रूप में प्रतिपादन किया है। जिस प्रकार लोक में पक्षियों के जोड़े वृक्ष पर बैठा करते हैं और उसके फलों को इच्छानुसार खाया करते हैं, या न खाया करते हैं- उसी लोकप्रसिद्ध बर्ताव के अनुरूप संसाररूपी वृक्ष के श्राश्रित जीवरूपी पक्षी को तो अपने किये कर्मों के फलों को भोगने वाला, परन्तु ब्रह्मरूप दूसरे पक्षी को कर्तृत्व भोक्तृत्व से दूर रहते हुवे केवल साक्षिमात्र कहा है। सो लौकिक व्यवहार शैली से जीव ब्रह्म सम्बन्धी रहस्य प्रकट करने के कारण उक्त सन्दर्भ लौकिक-भाषा का निदर्शन है।

इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में इन्द्रिय मन:, प्राण आदि को पुत्र और प्रजापति को पिता कहा गया है। जिस प्रकार लोक में पुत्रों के विवाद हो जाने पर वे अपने पिता से निर्णय मांगा करते हैं और पिता जी किसी विशेष योग्यता के अनुसार अमुक पुत्र को उच्चाधिकार प्रदान किया करते हैं। **क्रमश: ...**

# सुरों को साधने के लिए भीमसेन जोशी ने किया था कड़ा संघर्ष

**अनन्या मिश्रा**

जब भी भारतीय संगीत की बात होती है, तो आपके जहन में तमाम बड़े नाम आते होंगे। इन्हीं में से एक नाम पंडित भीमसेन जोशी का है। आपको बता दें कि भीमसेन जोशी किसी परिचय् के मोहताज नहीं है। आज ही के दिन यानी की 4 फरवरी को पंडित भीमसेन जोशी की बर्थ एनिवर्सरी है। वह एक शास्त्रीय गायक थे। जो भजे हरि को सदा, पिया मिलन की आस और मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे गानों के लिए याद किया जाता है।

कर्नाटक के गडग में 4 फरवरी 1922 को पंडित भीमसेन जोशी का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गुरुराज जोशी था, जोकि हाईस्कूल के हेडमास्टर थे और कन्नड़, अंग्रेजी व संस्कृत के विद्वान भी थे। वहीं भीमसेन अपने भाई-बहनों में सबसे बड़े थे। बेहद कम उम्र में भीमसेन के सिर से मां का साया उठ गया था। वहीं सौतेली मां ने उनका पालन-पोषण किया था। बचपन से ही उनको संगीत से काफी लगाव था।

आपको बता दें कि साल 1941 में महज 19 साल की उम्र में पंडित भीमसेन जोशी जी ने मंच पर पहली प्रस्तुति दी थी। वहीं 29 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम निकला। उनके इस एल्बम में हिंदी और कन्नड़ के कुछ धार्मिक गीत थे।

किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान से भीमसेन जोशी बचपन से ही प्रभावित थे। स्कूल जाने के रास्ते पर एक ग्रोमोफोन की दुकान थी। जहां पर ग्राहकों को गाने सुनाए जाते थे। उसी भीड़ में भीमसेन भी खड़े हो जाते थे। एक दिन इसी ग्रोमोफोन शॉप में राग वसंत में बृज देखन को, फगवा और पिया बिना नहि आवत चैन% ठुमरी सुना। यहीं से उनके मन में संगीत के प्रति रुचि आ गई।

एक दिन वह गुरु की तलाश में घर से निकल पड़े, इस दौरान वह करीब दो सालों कर बीजापुर, ग्वालियर और पुणे में रहे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दौरान उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। वहीं ग्वालियर में उस्ताद हाफिज अली खान से भीमसेन जोशी ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने भजन और ठुमरी आदि में भी महारत हासिल की थी।

जब भीमसेन जोशी ने 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था, तब उनके पास किराए तक के लिए पैसे नहीं थे। वहीं अपनी गायिकी के दम पर उन्होंने फ्री यात्रा की। जब वह गुरु की तलाश में घर से निकले तो उनको मंजिल का पता नहीं था। ऐसे में वह बिना टिकट के ट्रेन पर चढ़ गए और बीजापुर पहुंच गए। जब टीटी ने उनसे टिकट मांगा तो उन्होंने राग भैरव में %जागो मोहन प्यारे% और %कौन-कौन गुन गावे% सुनाकर टीटी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण समेत अन्य कई अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया।

वहीं लंबी बीमारी के बाद 24 जनवरी 2011 को पंडित भीमसेन जोशी का निधन हो गया था।

# बजट : लोक लुभावन भी और राजनीतिक भी

**उमेश चतुर्वेदी**

बजट की तैयारियों के बीच सोशल मीडिया पर एक खबर जुगनू की तरह आई और तत्काल लुप्त हो गई थी। जिसने जुगनू के उस प्रकाश को देखा और उसके संकेतों को समझने की कोशिश की थी, उन्हें इस बात का आभास हो गया था कि आम बजट में क्या होने जा रहा है। सोशल मीडिया पर आए उस समाचार में कहा गया था कि केंद्र सरकार के प्रति मध्य वर्ग पहले की तरह उत्साही नहीं है। किंचित वह केंद्र सरकार के कामकाज और सरकार की ओर से हो रही बेरूखी से वह परेशान और निराश है। सोशल मीडिया पर मध्य वर्ग की ऐसी प्रतिक्रियाओं पर मोदी की नजर रहती है। इसे देखते हुए उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा था कि वे लोगों से सीधा संवाद करें। सोशल मीडिया यही खबर थी। लेकिन इस खबर के संकेत साफ थे। आम बजट में मध्य वर्ग को राहत मिलने के आसार तभी दिखने लगे थे। निर्मला सीतारमण की ओर से बारह लाख 75 हजार रूपए तक की आय पर मिली आयकर छूट को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कुछ महीनों बाद देश की राजनीति की धड़कन माने जाने वाली मगध की धरती यानी बिहार में भी चुनाव होना है। निर्मला सीतारमण की ओर से मिली आयकर छूट से सरकारी कर्मचारियों की भी राजधानी मानी जाने वाली दिल्ली चुनाव पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार के बजट से खुश नहीं हैं और कह रहे हैं कि इस बजट से आम लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। इस बजट में बिहार को बहुत कुछ मिला है। निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्ताव में बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड का एलान किया है। इससे बिहार के मखाना किसानों को राहत मिलने के आसार है। इसके उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के अवसर बढ़ेंगे। जाहिर है कि इसका सीधा फायदा बिहार के ही लोगों को मिलेगा। बजट प्रस्तावों में मखाना निकालने के काम में लगे लोगों के लिए भी सरकारी राहत की बात की गई है। यानी मखाना उत्पादक, उसके वितरक और उसके कामगार, सबको राहत और मौका देने की बात की गई है। प्रस्तावित मखाना बोर्ड की एक और जिम्मेदारी होगी। वह किसानों को प्रशिक्षण और सहयोग भी देगा। साथ ही उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाले फायदों को भी सुनिश्चित करेगा।

वैसे देखें तो मध्य वर्ग को केंद्र सरकार ने इन बजट प्रस्तावों के जरिए एक लाख करोड़ रुपए का उपहार दिया है। इसमें 12 लाख 75 हजार रुपए की आमदनी वाले लोगों को जहां टैक्स में 80 हजार रुपए का फायदा हुआ है। आयकर में छूट की मांग अरसे होती रही है। पिछले कई बजट में ऐसी छूट नहीं मिलती थी तो लोग इसे लेकर निराश होते रहते थे। बहरहाल 16 लाख रुपए की आमदनी वाले लोगों को टैक्स में 50 हजार रुपए का फायदा हुआ है तो 18 लाख रुपए की आमदनी वाले को टैक्स में 70 हजार रुपए का लाभ दिख रहा है। इसी तरह 20 लाख रुपए की आमदनी वाले को 90 हजार रुपए का फायदा होगा तो 25 लाख रुपए की आमदनी वाले को एक लाख दस हजार रुपए का नए टैक्स नियमों से फायदा होगा। इसी तरह 50 लाख रुपए की आमदनी वाले को भी एक लाख दस हजार रुपए का फायदा हो रहा है। जाहिर है कि मध्य वर्ग को इससे फायदा होता नजर आ रहा है। वायस ऑफ बैंकिंग के प्रमुख अश्विनी राणा के अनुसार, टैक्स बचने से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आयेगा। इससे लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी। इससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

केन्द्रीय बजट में कृषि और महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। पीएम धन-धान्य योजना का प्रस्ताव किया गया है। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख किया गया। इससे किसानों को अपनी आय बढ़ाने के लिए लाभ होगा। भारतीय पोस्ट यानी इंडियन पोस्ट के दफ्तरों के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसका लाभ भी किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। एमएसएमई को राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जाएगा और नए वर्गीकरण तथा ऋण में भी बढ़ोतरी से लाभ होगा। एमएसएमई को भी क्रेडिट कार्ड देने की तैयारी है। इसके साथ ही बजट प्रस्तावों में राज्यों को शहरों में पूंजीगत योजनाओं में निवेश के लिए ऋण से जहां विकास होगा वहीं रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ ही, सक्षम आंगनवाड़ी 2.0 के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। ऊर्जा और जल मिशन पर भी फोकस किया गया है। रोजगार पैदा करने के लिए पर्यटन केंद्रों और आध्यात्मिक स्थलों का विकास अच्छा प्रयास है। सरकार ने इसी तरह बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को 75 से 100 प्रतिशत करने की तैयारी है। इससे बीमा क्षेत्र में विकास की उम्मीद है। अश्विनी राणा का कहना है कि इसके बावजूद सरकार को सचेत रहना होगा और बीमा कंपनियों को जनता को लूटने से बचाना होगा। सरकार को इसके लिए कड़ी निगरानी रखनी होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए नए कोड की घोषणा शीघ्र होगी। जीवन रक्षक दवाइयों पर आयात शुल्क समाप्त करने से रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। हर जिले में कैंसर के इलाज की सुविधा देना भी बड़ा फैसला है। इसके साथ ही मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी है। आम आदमी का सपना है अपने सिर पर अपना छत होना। इस बजट के जरिए लोगों को घर खरीदने में राहत का भी ऐलान किया गया है। इससे लोगों के साथ ही रियल एस्टेट को भी फायदा होगा। जिससे निर्माण क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।

बिहार का पटना हवाई अड्डा इन दिनों बेहद व्यस्त है। लेकिन वह छोटा पड़ रहा है। इसके विकास और उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी बजट प्रस्ताव किया गया है। इससे देश-विदेश में काम कर रहे बिहार के लोगों को सीधे फायदा होगा और उनकी अपनी माटी से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ ही, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, और उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है। इस संस्थान के जरिए समूचे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को मजबूती देने की तैयारी है। इसके द्वारा किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने की तैयारी तो है ही, उनकी आय में बढ़ोत्तरी का भी प्रस्ताव है। निर्मला सीतारमण के अनुसार, इस संस्थान के जरिए युवाओं को हुनरमंद बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही उन्हें उद्यमिता और रोजगार प्राप्त करने के अवसर पैदा करेगा। बिहार में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। इसके जरिए पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को भी आर्थिक सहायता मदद दी जा रही है। इसके जरिए उत्तरी बिहार के 50 हजार हेक्टेयर में सिंचाई की सहूलियत बढ़ेगी। इससे मिथिलांचल की कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। यूं तो हर बजट सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक भी होता है। लेकिन आयकर छूट और बिहार को मिलने वाली विशेष सहायता योजनाओं के संदर्भ में यह राजनीतिक बजट भी है। हालांकि इन पंक्तियों को लिखे जाने तक किसी ने इस नजरिए से बजट पर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन यह तय है कि इन प्रस्तावों से दिल्ली और बिहार के वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बजट के जरिए लोक को साधने के साथ ही आर्थिक स्थिति को भी बेहतर बनाने की कोशिश है। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि जीएसटी दरों में राहत मिलेगी, मध्य वर्ग को कर्ज मुक्ति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन कह सकते हैं कि यह बजट कुछ संदर्भों में लोकलुभावन है तो कुछ अर्थों में नहीं। इन अर्थों में यह राजनीतिक भी है और राजनीतिक हित साधने का साधन भी।

## आज का इतिहास

1920 लंदन से दक्षिण अफ्रीका के बीच पहली विमान सेवा शुरू हुई।
1929 एक लाखवां ए- फोर्ड मॉडल पूरा हुआ।
1948 उस समय सिलोन कहलाने वाला देश श्रीलंका ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ।।
1955 बगदाद संधि: इराक और तुर्की के बीच सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किया गया।
1969 यासिर अराफात को फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन का चेयरमैन चुना गया।
1974 गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले भौतिकशास्त्री सतेंद्र नाथ बोस का निधन हुआ।
1974 अमेरिकी अखबार उत्तराधिकारी और सोशलाइट पैटी हर्ट्स को सिम्बायनीज़ लिबरेशन आर्मी द्वारा विदडेक किया गया, जो बाद में स्टॉकहोम सिंड्रोम के सबसे प्रसिद्ध मामलों में शामिल हो गया।
1974 अनंतिम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने एक मोटर कोचकार्यिंग ऑफ-ड्यूटी ब्रिटिश सशस्त्र बल के कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों पर बमबारी की, जिसमें बारह मारे गए और पचास से अधिक घायल हो गए।
1976 अमेरिकी देशों ग्वाटेमाला और होंडूरास में आये भीषण भूकंप में 22000 लोगों की मौत हुई।
1992 वेनेजुएला की सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यूगो शावेज कार्लोस आंद्रेस पेरेज की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अपने प्रयास में असफल रहे।
1994 सूडान के खारतुम में मस्जिद पर सशस्त्र हमले में 20 लोगों की मौत।
1995 सैंड्रा वोल्कर, महिला यूरोपीय तैराक 50 मीटर बैक स्टोक तैरती है जो लगभग 27.77 सेकंड दर्ज की गई थी।
1997 लेबनान जाने वाले रास्ते में 2 इजरायली सेना-परिवहन हेलीकॉप्टर टकराने से 73 लोगों की मौत हो गयी।
1997 अमेरिका के सचिव मार्गरेट अलब्राइट ने घोषणा की कि उन्होंने सिर्फ यह पाया कि उनके दादा-दादी यहूदी थे।
1998 दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स के चेहरे पर एक पाई फेंकी गई।
1999 गिनी के एक 23 वर्षीय आप्रवासी अमादौ डायलो को न्यूयॉर्क शहर के पुलिस विभाग के सादे-कपड़े वाले अधिकारियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई।
2004 मार्क जुकरबर्ग ने सोशल नेटवार्किंग वेबसाइट फेसबुक की स्थापना की।

# सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट से भारत निर्माण को मिलेगी गति

**कमलेश पांडे**

आम बजट 2025 एक सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट है। यह कई मायने में सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी भी है। खासकर ताजा बजट प्रस्तावों के माध्यम से मध्यम वर्ग को जो भारी कर राहत प्रदान किया गया है और आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपया तक कर दिया गया है, उससे अर्थव्यवस्था को विभिन्न कोणों से मजबूती मिलने के आसार प्रबल हैं। कुल मिलाकर यह आम आदमी का बजट है, जो गरीबों, युवाओं, अन्नदाता किसानों और नारी शक्ति को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है।

सच कहा जाए तो यह आम बजट विकसित भारत यानी हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है, जिसमें किसानों, गरीबों के साथ-साथ मध्यम वर्ग पर भी ध्यान दिया गया है। वहीं, महिला और बच्चों की शिक्षा, उनके पोषण व स्वास्थ्य पर भी फोकस किया गया है। इस बजट में स्टार्टअप, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट तक, यानी कि अर्थव्यवस्था की समुन्नति के हर क्षेत्र को समाहित किया गया है। इस प्रकार यह बजट मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का व्यापक रोडमैप है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक, यह बजट भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। इसके माध्यम से उन्होंने युवाओं के लिए कई क्षेत्र खोले हैं। जिससे आम नागरिक विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने जा रहा है। यह बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है, जो बचत, निवेश, खपत और विकास को तेजी से बढ़ाएगा।

आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर होता है कि सरकारी खजाना कैसे भरा जाएगा, लेकिन यह बजट उसके ठीक उलट है। यह बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास में कैसे भागीदार बनेंगे...इस बात की चिंता करता है। इस बजट में सुधार हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। विशेष कर यह बजट देश के विकास में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान सुनिश्चित करेगा।

यूँ तो बजट में हर तरह से रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, फिर भी मैं उन सुधारों की चर्चा करना उचित समझता हूं जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। हम सभी जानते हैं कि शिप बिल्डिंग निर्माण सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। वहीं, देश में पर्यटन विकास की बहुत संभावनाएं हैं। इसलिए पहली बार होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर होटल बनाए जाएंगे। इससे आतिथ्य क्षेत्र को ऊर्जा मिलेगी, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है।

वहीं, इस बजट में एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए %ज्ञान भारत मिशन% शुरू किया गया है। इसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, यानी तकनीक का भरपूर उपयोग किया जाएगा। वहीं, इस बजट में किसानों के लिए की गई घोषणा कृषि क्षेत्र और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई क्रांति का आधार बनेगी। किसान क्रेडिट कार्ड% की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी, जिससे उन्हें और मदद मिलेगी।

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 फरवरी, 2025, दिन शनिवार को संसद में बजट पेश किया, जो उनका लगातार 8वां बजट था। यह बजट आर्थिक सर्वेक्षण के अनुरूप रहा। क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास को राहत देते हुए न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये सालाना तक की इनकम को आयकर के दायरे से बाहर रखने का ऐलान किया। इससे नौकरीपेशा वर्ग के करोड़ों लोगों को फायदा होगा।

वहीं, उन्होंने किसान और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। स्वास्थ्य और रोजगार पर हमारा खास ध्यान है। युवाओं को रोजगार देना सरकार की प्राथमिकता है। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10

व्यापक क्षेत्रों में हैं, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 सालों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने दुनियाभर का ध्यान आकर्षित किया है। इस दौरान भारत की क्षमता को लेकर विश्वास बढ़ा है। इसी कड़ी में अब बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बेहतर बनाने के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इस कार्य में लगे लोगों को एफपीओ के रूप में संगठित किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा, स्टार्टअप के लिए लोन गारंटी शुल्क कम करेंगे। एमएसएमई के लिए लोन 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से 5 लाख की गई है। डेयरी और फिशरी के लिए अब पांच लाख तक का लोन दिया जाएगा। इससे इस वर्ष का बजट मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने, एमएसएमई को समर्थन देने, रोजगार आधारित विकास को सक्षम करने, लोगों की अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करने, ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। यह बजट सरकार की राजस्व और व्यय रणनीति के लिए एक सामान्य रोड मैप प्रदान करता है। बजट 2025 युवाओं, महिलाओं और किसानों पर केंद्रित है।

वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि यह बजट सरकारी प्रयासों को जारी रखता है- विकास में तेजी लाने के लिए, सुरक्षित समावेशी विकास के लिए, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू भावनाओं को ऊपर उठाने के लिए, भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। आम बजट में जिन विषयों पर फोकस किया गया, उनमें मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना, एमएसएमई को समर्थन रोजगार आधारित विकास को सक्षम बनाना प्रमुख हैं।

वहीं, लोगों की अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करना और निर्यात का समर्थन करना भी शामिल हैं। इस बजट में नवप्रवर्तन का पोषण व पीएम धन्य-धान योजना की घोषणा की गई है। वहीं, स्टार्टअप की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ की गई। इस बजट में 5 नए परमाणु रियक्टर बनाने की घोषणा क्रांतिकारी कदम है। वहीं, मुद्रा योजना में होम स्टे के लिए योजना, सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को 10त्न से बढ़ाकर 12.5त्न कर दिये जाने का सबको लाभ मिलेगा।

वहीं, कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजीगत लाभ पर छूट की सीमा बढ़ाकर ?1.25 लाख प्रति वर्ष कर दी गई। जबकि कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर को 15त्न से बढ़ाकर 20त्न कर दिया गया। वहीं, वायदा और विकल्प पर प्रतिभूति लेनदेन कर बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना की घोषणा की गई। जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है।

इस बजट में प्रत्येक प्रशिक्षु को 12 महीनों के लिए वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल से परिचित कराया जाएगा और उन्हें ?5,000 का भत्ता और ?6,000 की एकमुश्त सहायता मिलेगी। वहीं, श्रमिकों, महिलाओं और निम्न आय वर्ग के लिए किफायती आवास यानी सरकार ने लोगों के सिर पर छत सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। वहीं, औद्योगिक श्रमिकों के लिए, व्यवहार्यता अंतर निधि और प्रमुख उद्योगों की प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से छात्रावास-प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास की सुविधा दी जाएगी।

कार्यबल में अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं के छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। सरकार क्षेत्रीय और मंत्रिस्तरीय लक्ष्यों के साथ निर्यात सहायता मिशन शुरू करेगी। मिशन को वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। निर्यात सहायता मिशन विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने के लिए निर्यात ऋण, सीमा पार फैक्टरिंग समर्थन और एमएसएमई को समर्थन तक आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।

कुल मिलाकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेता जहां इस बजट की तारीफ कर रहे हैं और इसे लोक कल्याणकारी बता रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता इसकी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि, वित्त मंत्री ने 4 इंजनों की बात की। वे हैं- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। ये इतने सारे इंजन हैं कि बजट पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। उन्होंने आगे कहा, %ऐसा लगता है कि बजट में बिहार को घोषणाओं का खजाना मिल गया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि साल के अंत में वहां चुनाव होने हैं। लेकिन एनडीए के दूसरे स्तंभ यानी आंध्र प्रदेश की इतनी बेरहमी से अनदेखी क्यों की गई?%

वहीं, कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने कहा, %हमें यह देखने की जरूरत है कि जो वादे पहले के बजट में किये गये थे क्या वे पूरे हुए? स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए बजट को पढ़ने की जरूरत है। बिहार को लेकर हुई घोषणाएं स्वाभाविक थीं। यह राजनीति है।%

जबकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, %मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह भारत सरकार का बजट था या बिहार सरकार का? क्या आपने केंद्रीय वित्त मंत्री के पूरे बजटीय भाषण में बिहार के अलावा किसी अन्य राज्य का नाम सुना?

# सरकार ने किसानों-महिलाओं, युवाओं कॉरपोरेट, बुजुर्गों का भी रखा ध्यान

**मनीषा प्रियम**

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आम बजट को संतुलित बनाने की भरसक कोशिश की, जिसमें वह सफल भी रही हैं, लेकिन किसी एक राज्य पर यदि उनका ज्यादा फोकस दिखा, तो वह बिहार ही है। अपने बजट भाषण में सबसे पहले उन्होंने कृषि संबंधी विषयों को ही रखा, जो सरकार की कृषि विकास को लेकर प्रतिबद्धता को ही दर्शाता है। बाढ़ के मामले में उन्होंने बिहार की आपदा पर विशेष ध्यानाकर्षण किया और कहा कि सिंचाई के कार्यक्रमों में बढ़ोतरी भी होगी और कोसी नदी के प्रबंधन का भी काम होगा। उन्होंने यह भी बतलाया कि बिहार में बाढ़ के कारक कोसी नदी के अपर कमांड के इलाके हैं, जो नेपाल में स्थित हैं। हालांकि उन्होंने बाढ़ ग्रसित अन्य राज्यों, जैसे असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड के विकास की भी बात की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के भावी विकास में पर्यावरण प्रबंधन के बाद पर्यटन का महत्व बहुत रहेगा। यहां भी फिर से उन्होंने बिहार के प्राचीन मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों का जिक्र किया, मसलन, गया का विष्णुपद मंदिर तथा बोधगया का महाबोधि मंदिर और राजगीर। सरकार, काशी विश्वनाथ की तर्ज पर यहां भी कॉरिडोर बनाएगी और पर्यटन का प्रचार-प्रसार करेगी। इसी के साथ उन्होंने ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान की बात कही और यह भी कहा कि इसे विश्वस्तरीय दर्जा दिया जाएगा। बिहार की तरह ही ओडिशा में भी ऐसी नीतियां अपनाई जाएंगी। बिहार का नाम एक बार फिर?आया, जब उन्होंने यह कहा, आईआईटी, पटना में सीटें बढ़ाई जाएंगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट स्थापित किया जाएगा। सीतारमण ने नए हवाई अड्डों का भी जिक्र किया और फिर से यह कहा कि बिहार में नए हवाई अड्डे भी बनाए जाएंगे और पटना के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे का विस्तार व नवीनीकरण किया जाएगा। यानी जैसे अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, वैसे ही सरकार की पैनी नजर बिहार पर बनी हुई है। सरकार के निहितार्थ तो स्पष्ट ही हैं, इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और पहली बार भाजपा राज्य में कमान संभालने की स्थिति में है। ऐसे में सरकारी कृपा दृष्टि का बिहार पर केंद्रित होना राजनीतिक न्याय और नीति के संगत है। हालांकि बजट की सबसे लुभावनी बात मध्य वर्ग पर सरकार की कृपा दृष्टि ही रही। अगर आप एक लाख रुपये महीना कमाते हैं, तो आपको कोई कर नहीं देना होगा, अब भला ऐसी घोषणा किसका दिल नहीं जीतेगी। इससे सरकार ने देश के उस मध्य वर्ग को आकर्षित करने की कोशिश की है, जो बाजार अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कहा जा सकता है कि इस बजट से ताली बिहार में तो बजेगी ही, लेकिन बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, कॉरपोरेट, बुजुर्गों इत्यादि का ध्यान रखा गया है, इसलिए कुल मिलाकर सभी खुश हैं। इसका असर आसन्न दिल्ली चुनाव पर भी दिखे, तो हैरत नहीं।

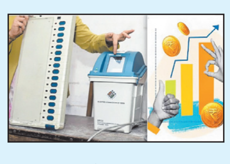

# सीतारमण के गेम चेंजर बजट में मध्यम वर्ग को बोनस

**विनोद पाठक**

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक चार दिन पहले केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की कि 12.75 लाख रुपए सालाना आय पर अब टैक्स नहीं देना होगा। एक अनुमान के मुताबिक देश की 31 प्रतिशत आबादी मध्यम वर्ग की है। हालांकि, नए इनकम टैक्स स्लैब का फायदा नई इनकम टैक्स रिजीम चुनने वालों को होगा।

वित्त मंत्री ने अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल लाने की बात भी कही, जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से की जा रही है। इसी साल के अंत में बिहार में भी विधानसभा चुनाव हैं। वित्त मंत्री में बिहार के मतदाताओं पर भी फोकस किया है। वित्त मंत्री ने बहुत अधिक लोकलुभावन घोषणा करने के बजाय बजट को सुधारवादी रखा है। इसे गेम चेंजर बजट कहा जा सकता है।

पहले बात बिहार की। राज्य में मखाना बोर्ड बनेगा, जिससे राज्य के छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा पहुंचेगा। तीन नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे और पटना व बेहटा एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी। पटना आईआईटी का विस्तार सरकार कराएगी। अन्य घोषणाओं से भी बिहार को लाभ मिलेगा। दिल्ली में नीतीश कुमार के सहयोग से चल रही मोदी सरकार ने बिहार का ख्याल रखा है।

दिल्ली में बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग के मतदाता हैं, उनके लिए नया इनकम टैक्स स्लैब निश्चित रूप से लुभाने वाला है। हालांकि, इनकम की रियायतों से सरकार को एक लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा और अप्रत्यक्ष कर में कमी से 2600 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होने आने वाली है।

निर्मला सीतारमण के फोकस पर किसान भी रहे। तीन कृषि कानूनों के रद्द होने और किसानों के लगातार आंदोलनरत रहने की गंभीरता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

भली-भांति समझते हैं। इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख की गई है। इससे 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों आदि को लाभ मिलने वाला है। दालों के लिए एक और योजना की घोषणा की गई है। हालांकि, पिछली योजनाओं के नतीजे सामान्य ही रहे हैं। दरअसल, सरकार के आगे दलहन का उत्पादन बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि साल-दर-साल दलहन का आयात बढ़ रहा है।

वर्ष 2023-24 में देश ने 4.65 मिलियन मीट्रिक टन दालों का आयात किया था, जो वित्तीय वर्ष 2018-19 के बाद से सबसे अधिक आयात है। दालों का आयात 93 प्रतिशत बढ़कर 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सरकार खेती के लिए धन-धान्य कृषि योजना लेकर आ रही है, जिसे राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू किया जाएगा। पहले चरण में 100 जिलों को लिया जाएगा। हालांकि, इसे लागू करना राज्यों पर निर्भर होगा और गैर भाजपा राज्यों में कैसे यह योजना लागू होगी? यह सरकार के आगे चुनौती होगी।

वित्त मंत्री का फोकस रोजगार बढ़ाने पर भी है। खासकर निजी क्षेत्र के रास्ते रोजगार के नए अवसर पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को लेकर घोषणाएं की हैं। अभी एमएसएमई सेक्टर 7.7 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। अब एमएसएमई की गारंटी 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ करने से नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

नई घोषणा से 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण एमएसएमई को मिलेगा। खिलौना निर्माण को लेकर पिछले बजटों में वित्त मंत्री ने घोषणाएं की थीं। अब मेक इन इंडिया के तहत इसे आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार देश में खिलौना निर्माण का ग्लोबल हब बनाकर चीन को सीधी चुनौती देना चाहती है। साथ ही, इससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जिसमें 31 करोड़ से अधिक आगंतुक आ चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग अयोध्या और काशी भी जा रहे हैं। देश के अन्य पर्यटन स्थलों पर देश-विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। सरकार पर्यटन की क्षमताओं से परिचित है, इसलिए बजट में 50 पर्यटन स्थलों के विकास की घोषणा वित्त मंत्री ने की है।

हालांकि, यह भी राज्यों की भागीदारी से किया जाएगा। नए पर्यटन स्थलों के विकास से भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यदि सुधारों की बात की जाए तो बीमा क्षेत्र में अब 100 प्रतिशत विदेशी निवेश की छूट मिलेगी। पहले यह 74 प्रतिशत थी। ई-कॉमर्स डिलीवरी आदि के काम से जुड़े गिग कर्मचारियों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम का ऐलान किया गया है। यह क्या होगी? यह अभी स्पष्ट नहीं है।

कुल मिलाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बहुत अधिक लुभावनी योजनाओं से बचने की कोशिश की है। रोजगार के नवीन अवसर पैदा करने की कोशिश की गई है। राजकीय राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा गया है और इसे वित्त वर्ष 2026 में 4.4 प्रतिशत रखने का संकल्प लिया गया है। वित्त मंत्री सरकारी खर्च में कटौती करने के मूड में नजर आती हैं। बजट नई दिशा और नए अवसरों को खोलने वाला है।

# विज्ञान और तकनीक के लिए बजट में आवंटन

**शशांक द्विवेदी**

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में लगातार अपना 8वां केंद्रीय बजट पेश करते हुए युवाओं के भविष्य और अवसरों को बढ़ाने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। ये फैसले शिक्षा, स्टार्टअप, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवाओं को नए मौके देने के उद्देश्य से किए गए हैं। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपये का फंड स्थापित करेगी। इससे नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलेगी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।

यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है. चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए कुल 1.48 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप प्रदान की जाएंगी, जिससे उच्च शिक्षा और शोध को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ज्ञान भारत मिशन के तहत 1 करोड़ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पांडुलिपियों (मैन्युस्क्रिप्ट) को डिजिटलाइज करेगी, जिससे देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित किया जा सके।

पीएम मोदी ने हाल में ही माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला समेत देश के और बाहरी आईटी इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की थी। सरकार अगले पांच सालों में एआई मिशन को और विस्तार देने की योजना को बढ़ाने के संकेत देते हुए आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस के इस्तेमाल, डेटा प्राइवेसी जैसी चिंताओं के मद्देनजर एक फ्रेमवर्क सामने रखने कि उम्मीद थी।

यह बजट ऐसे समय आया है जब दुनिया में एआई की धूम मची है। अमेरिका और चीन एआई की लड़ाई में एकदूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। ऐसे में आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस के लिए सिर्फ 500 करोड़ देना ऊंट के मुहं में जीरे जैसा है। एआई में सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. साथ में 3 एआई एक्सिलेंस सेंटर लगाए जाने की बात कही गई है।

इस बजट में हेल्थकेयर ,सौर ऊर्जा, ईवी, पावर और माइनिंग,फूड टेक्नोलॉजी पर भी पूरा जोर है। सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को फ्री लोन देने की भी बात कही है। वित्त मंत्री ने ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त कैपिटल गुड्स और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 कैपिटल गुड्स जोड़ने का प्रस्ताव दिया है।

सरकार 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड' पहल के तहत स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के लिए नई योजनाएं लागू करेगी. युवाओं को आधुनिक कौशल (स्किल्स) से लैस करने के लिए देशभर में 5 राष्ट्रीय स्तर के स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिएसभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा.

बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की गई है। आईआईटी पटना को भी वित्त पोषित करके इसकी क्षमता का विस्तार करने का एलान किया गया है। इसके अलावा 5 आईआईटी में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जाएगा और इनकी सीटों की संख्या में 6,500 की बढ़ोतरी की जाएगी।

मेडिकल की सीटों में में 75 हजार का इजाफा 5 साल में करने का वादा किया गया है। सरकार ने 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जो 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, और गणित शिक्षा को बढ़ावा देंगी। इससे बच्चों को तकनीकी कौशल में बेहतर शिक्षा मिल सकेगी और वे भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे।

परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए ,20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रियक्टर्स (एसएमआर) के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा।

2033 तक 5 स्वदेश विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव। 25 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष की स्थापना का प्रस्ताव। इसमें सरकार का योगदान 49 प्रतिशत होगा। शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को करना होगा।

इस बार के बजट में मोदी सरकार ने एमएसएमई के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन गठन की बात कही है। इनके माध्यम से अब क्लीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिए जाने पर जोर है। एमएसएमई को अब 5 की जगह 10 करोड़ रुपए तक का कवर दिया जाएगा। देश के निर्यात में एमएसएमई की भागीदारी 45त्न हो चुकी है। स्टार्टअप को भी 20 करोड़ रुपए तक का कवर दिया जाएगा। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की स्थापना की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में देश में एमएसएमई सेक्टर का 36त्न योगदान है। इनकी संख्या अभी 5.7 करोड़ है और इसमें 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे।

# बजट पर मिली-जुली प्रतिक्रिया और टीएमसी का नजरिया

**प्रभाकर मणि तिवारी**

शनिवार को संसद में पेश केंद्रीय बजट पर पश्चिम बंगाल में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने इसे गहरी साजिश% बताया है। पार्टी ने इसमें बंगाल की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इसे %बिहार का बजट% करार दिया है। दूसरी ओर, मध्यवर्ग ने आयकर छूट की सीमा बढ़ाए जाने पर संतोष तो जताया है लेकिन साथ ही उनका कहना है कि महंगाई कम होती तो ज्यादा राहत मिलती। राज्य के पूर्व वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आर्थिक सलाहकार अमित मित्र का कहना था कि बीमा के क्षेत्र में सौ फीसदी विदेशी निवेश का रास्ता तो खोल दिया गया है। लेकिन प्रीमियम की रकम पर 18 फीसदी जीएसटी वसूली जा रही है। क्या विदेशी निवेशकों की सहूलियत के लिए ही ऐसा किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी प्रीमियम पर जीएसटी खत्म करने की मांग कर चुकी हैं। लेकिन इसे खत्म नहीं किया गया है। अमित मित्र का कहना था कि आयकर में छूट भले दी गई है लेकिन भारत में कितने लोगों की मासिक कमाई एक लाख रुपए है? आम लोगों से जुड़े मुद्दों को बजट में कोई तरजीह नहीं दी गई है। तृणमूल कांग्रेस सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि भाजपा सरकार के बीते दस साल के शासनकाल के दौरान बंगाल को केंद्रीय बजट में कुछ भी नहीं मिला है। बीते साल जुलाई में पेश बजट में भी बिहार और आंध्र प्रदेश को जमकर सौगात दी गई थी। इस साल भी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार की झोली भर दी गई है। पार्टी के महासचिव कुणाल घोष कहते हैं कि यह आम लोगों का बजट नहीं है। सरकार ने 12 लाख तक आयकर में छूट भले दी है लेकिन इतनी कमाई कितने लोगों की होती है। ऐसे लोगों के लिए यह छूट बेमानी है। सीधे कहें तो यह केंद्रीय नहीं बल्कि बिहार का बजट है। कोलकाता में एक सरकारी कर्मचारी नाम नहीं बताने की शर्त पर कहते हैं कि आयकर में छूट की उम्मीद तो कई साल से थी। लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद यह कितना प्रभावी रहेगा, यह समझना मुश्किल है. केंद्र सरकार को इसके साथ ही महंगाई कम करने की दिशा में बी ठोस पहल करनी चाहिए। बर्दवान जिले की एक गृहिणी सुनंदा सेनगुप्ता कहती है कि सरकार को दैनिक उपयोग की चीजें और रसोई गैस की कीमतों में कटौती पर ध्यान देना चाहिए था। हर महीने बढ़ने वाली महंगाई से घर का बजट बिगड़ा ही रहता है। इसके अलावा हम लोग कर के दायरे में नहीं आते। इसलिए आयकर छूट से हमारे रोजमर्रा के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आसनसोल में अदरक का कारोबार करने वाले आदित्य घराई कहते हैं कि हमारी साल में 12 लाख कमाई ही नहीं है तो कर छूट से हमें क्या फायदा। हमें तो अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलनी चाहिए। बांकुड़ा में एक सरकारी कर्मचारी प्रमोद कुमार पाल कहते हैं कि आयकर में छूट के बाद अब अगले साल वो इसके दायरे से बाहर निकल जाएंगे यानी अब आयकर का भुगतान नहीं करना होगा। लेकिन दिन-ब-दिन बढ़ती महंगाई और स्कूल फीस से लेकर तमाम वस्तुओं की बढ़ती कीमतें आम लोगों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। कोलकाता के एक खुदरा व्यापारी दीपक मंडल कहते हैं कि इस बजट से एक खास वर्ग के लोगों को ही फायदा हुआ है। राज्य में ज्यादातर लोगों की आय साल में 10 लाख से कम ही है. उनको आयकर में छूट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बजट में राज्य के आम लोगों के लिए कुछ नहीं है।

# घर में सुख-शांति और सकारात्मकता के लिए रखें भगवान हनुमान की खास तस्वीरें !

**हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा और शांति बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में भगवान हनुमान जी की तस्वीरें भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हनुमान जी को संकटमोचक कहा जाता है, और उनकी पूजा से न केवल कठिनाइयों का नाश होता है, बल्कि घर में सुख-शांति, समृद्धि और सकारात्मकता भी बनी रहती है।**

मानसिक शांति और क्रोध पर नियंत्रण के लिए

अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में मानसिक शांति बनी रहे और घर के सदस्यों का क्रोध नियंत्रण में रहे, तो हनुमान जी की ध्यान मुद्रा वाली तस्वीर घर के उत्तर-पूर्व दिशा में लगाएं। हनुमान जी की इस तस्वीर को देखकर मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। ध्यान मुद्रा में हनुमान जी का चित्र आत्मसंयम और शांति का प्रतीक है। यह चित्र आपको धैर्यवान और शांतचित्त रहने में मदद करता है।

### अच्छे स्वास्थ्य के लिए

अगर घर के सदस्यों को बार-बार स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हनुमान जी की वह तस्वीर लगाएं जिसमें वे संजयवनी बूटी ले जाते हुए दिखाई देते हैं। यह तस्वीर भी घर की उत्तर-पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। यह न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को भी दूर करती है। यह चित्र स्वस्थ जीवन और बल का प्रतीक है।

### बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए

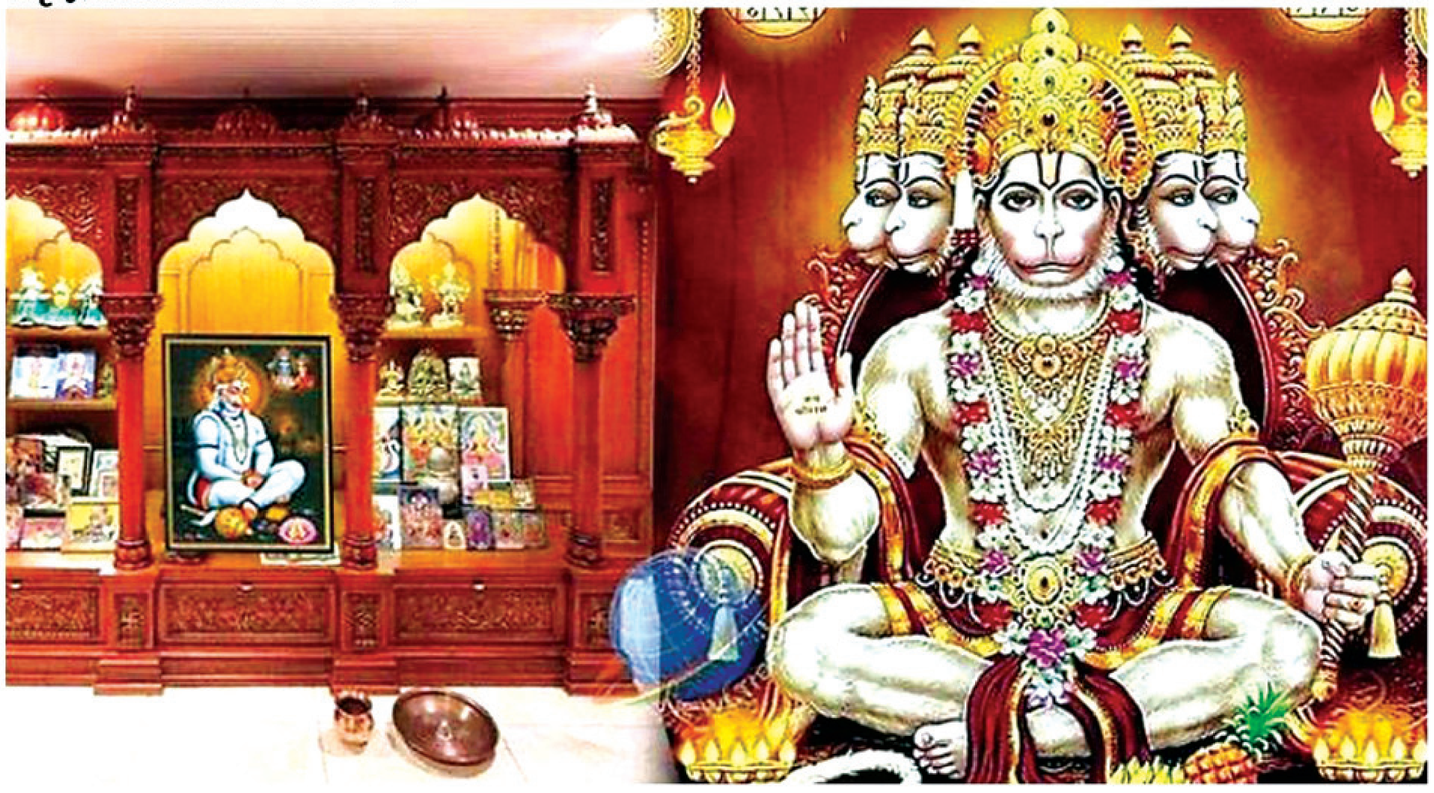

अगर आप अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचाना चाहते हैं, तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर घर के दक्षिण-पश्चिम दिशा में लगाएं। पंचमुखी हनुमान जी की यह तस्वीर सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इसे घर में लगाने से घर पर कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डालती और घर का हर सदस्य सुरक्षित महसूस करता है। यह चित्र शत्रुओं से बचाने और जीवन में साहस बनाए रखने में भी मदद करता है।

### धन और समृद्धि के लिए

अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और समृद्धि बनी रहे, तो सूर्य देव को प्रणाम करते हुए हनुमान जी की तस्वीर घर के दक्षिण दिशा में लगाएं। सूर्य देव को प्रणाम करते हुए हनुमान जी की तस्वीर से घर में धन का प्रवाह बना रहता है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। यह तस्वीर जीवन में प्रगति और समृद्धि का प्रतीक है।

### तस्वीरें लगाने में ध्यान रखने योग्य बातें

1. तस्वीर को साफ-सुथरी जगह पर लगाएं और उसके आस-पास गंदगी न रखें।
2. हनुमान जी की तस्वीर को रोजाना प्रणाम करें और अगर संभव हो तो दीपक जलाएं।
3. तस्वीर को हमेशा सकारात्मक भावना और श्रद्धा के साथ लगाएं।
4. तस्वीर को ऐसी जगह पर लगाएं जहां हर कोई आसानी से देख सके और वह दिशा वास्तु के अनुसार सही हो।

भगवान हनुमान की तस्वीरें केवल धार्मिक महत्व ही नहीं रखतीं, बल्कि वास्तु और सकारात्मक ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इन तस्वीरों को सही दिशा और सही भावना के साथ अपने घर में लगाते हैं, तो यह आपके जीवन में सुख-शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुरक्षा लाने में मददगार साबित होगी।

# सीढ़ियों के नीचे की जगह का करें स्मार्ट इस्तेमाल

## इंटीरियर डिज़ाइनर के खास टिप्स

**घर में जगह का सही उपयोग करना हर इंटीरियर डिज़ाइनर की प्राथमिकता होती है। अक्सर घरों में सीढ़ियों के नीचे की जगह खाली पड़ी रहती है, जिसे कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन, यह जगह न केवल आपकी जरूरतों को पूरा करने का, बल्कि आपके घर को और आकर्षक बनाने का मौका भी देती है। अगर आप भी अपने घर की सीढ़ियों के नीचे के कोने को उपयोगी और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो ये टिप्स आपके काम आ सकते हैं।**

### स्टोरेज एरिया बनाएं

सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज एरिया बनाना सबसे आम और उपयोगी विकल्प है। आप इस जगह पर अलमारियां या कैबिनेट्स डिज़ाइन करवा सकते हैं। यह जगह जूतों, किताबों, या अन्य सामान को व्यवस्थित रखने के लिए परफेक्ट है। स्लाइडिंग दरवाजों के साथ मॉड्यूलर स्टोरेज डिज़ाइन इसे और भी फंक्शनल बना सकता है।

### मिनी लाइब्रेरी या बुकशेल्फ का सेटअप करें

अगर आप किताबों के शौकीन हैं, तो सीढ़ियों के नीचे की जगह को मिनी लाइब्रेरी में बदल सकते हैं। दीवार पर फिटेड बुकशेल्फ डिज़ाइन करवाकर आप न केवल अपने घर को स्टाइलिश बना सकते हैं, बल्कि किताबों को व्यवस्थित रखने का बेहतरीन समाधान भी पा सकते हैं।

### वर्कस्पेस या होम ऑफिस

आज के समय में वर्क फ्रॉम होम आम हो गया है। सीढ़ियों के नीचे का कोना एक कॉम्पैक्ट होम ऑफिस के लिए एकदम सही हो सकता है। यहां एक टेबल, कुर्सी और कुछ शेल्फ लगाकर आप इसे एक कार्यक्षेत्र में बदल सकते हैं। अच्छी रोशनी और दीवारों पर पिनबोर्ड या सजावट से इसे और भी आकर्षक बनाएं।

### रीडिंग नूक (आरामदायक कोना)

आराम से बैठकर पढ़ने या चाय का आनंद लेने के लिए सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा रीडिंग नूक बनाया जा सकता है। इसके लिए एक छोटा सोफा, कुशन और साइड टेबल काफी होंगे। यह जगह परिवार और दोस्तों के लिए भी आरामदायक बन सकती है।

### मिनी गार्डन या प्लांट डिस्प्ले

अगर आप हरियाली पसंद करते हैं, तो सीढ़ियों के नीचे की जगह को मिनी गार्डन में बदल सकते हैं। यहां छोटे गमले, सुकुलेंट्स और दीवार पर हैंगिंग प्लांट्स लगाकर इसे एक आकर्षक ग्रीन स्पेस में तब्दील करें। सही लाइटिंग और वॉटरप्रूफिंग का ध्यान रखें।

### बच्चों के खेलने की जगह

सीढ़ियों के नीचे बच्चों के लिए एक छोटा प्ले जोन डिज़ाइन किया जा सकता है। यहां कुशन, खिलौनों के बॉक्स और दीवार पर सजावटी पेंटिंग्स से इसे उनके लिए मजेदार और सुरक्षित बनाया जा सकता है।

### पालतू जानवरों के लिए कोना

अगर आपके पास पालतू जानवर हैं, तो सीढ़ियों के नीचे का स्पेस उनके लिए एक आरामदायक कोना बन सकता है। यहां उनका बिस्तर, खाने के बर्तन और खिलौने रखे जा सकते हैं। यह उन्हें उनकी खुद की एक जगह देने का शानदार तरीका है।

### वाइन स्टोरेज या बार काउंटर

अगर आप वाइन कलेक्टर हैं या दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, तो सीढ़ियों के नीचे वाइन स्टोरेज या मिनी बार काउंटर डिज़ाइन कर सकते हैं। यहां एक स्टाइलिश कैबिनेट और काउंटर लगाकर इसे एक आकर्षक एंटरटेनमेंट स्पेस बनाया जा सकता है।

### डिस्प्ले यूनिट या गैलरी

सीढ़ियों के नीचे एक डिस्प्ले यूनिट बनाकर आप अपने घर की खासियत को बढ़ा सकते हैं। इसमें आर्ट पीस, पारिवारिक तस्वीरें या सजावटी सामान रख सकते हैं। सही लाइटिंग के साथ यह कोना आपके मेहमानों का ध्यान खींचने वाला बन जाएगा।

### छोटे गेस्ट रूम का विकल्प

अगर आपके घर में जगह की कमी है, तो सीढ़ियों के नीचे एक छोटे गेस्ट रूम का सेटअप किया जा सकता है। यहां एक सिंगल बेड और कुछ जरूरी फर्नीचर रखकर इसे आरामदायक बनाया जा सकता है।

सीढ़ियों के नीचे की जगह को सही तरीके से उपयोग करके आप न केवल अपने घर को व्यवस्थित रख सकते हैं, बल्कि इसे एक नया और आकर्षक रूप भी दे सकते हैं। चाहे स्टोरेज हो, रीडिंग नूक, मिनी गार्डन या होम ऑफिस, आपके घर की इस अनदेखी जगह को स्मार्ट डिज़ाइन से काम में लाने के ढेरों विकल्प हैं। एक

इंटीरियर डिज़ाइनर के रूप में मेरा मानना है कि हर इंच का सही उपयोग करना न केवल व्यावहारिक है, बल्कि आपके घर की सुंदरता और आरामदायकता को भी बढ़ाता है।

तो अगली बार अपने घर को डिज़ाइन करते समय सीढ़ियों के नीचे की जगह को भी एक नई पहचान दें!

### 1. स्टोरेज एरिया बनाएं

- एक स्मार्टली डिज़ाइन किया हुआ मॉड्यूलर स्टोरेज, जिसमें स्लाइडिंग दरवाजे हैं।
- दिखाएं कि जूतों और किताबों के लिए अलग-अलग खांचे किस तरह उपयोग किए जा सकते हैं।

### 2. मिनी लाइब्रेरी या बुकशेल्फ

- दीवार पर फिटेड बुकशेल्फ के साथ एक स्लीक डिज़ाइन।
- किताबों के साथ कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, जैसे छोटे प्लांट्स या फोटो फ्रेम।

### 3. वर्कस्पेस या होम ऑफिस

- एक कॉम्पैक्ट टेबल और कुर्सी के साथ वॉल-माउंटेड शेल्फ।
- लैपटॉप, पिनबोर्ड, और सुंदर वॉल डेकोर के साथ वर्कस्पेस का सेटअप।

### 4. रीडिंग नूक (आरामदायक कोना)

- एक छोटी बेंच या सोफा, जिसमें कुशन और साइड में लैंप रखा हो।
- आरामदायक सेटअप, जिसमें किताबें और एक कॉफी मग रखा हो।

### 5. मिनी गार्डन या प्लांट डिस्प्ले

- सीढ़ियों के नीचे छोटे गमले, सुकुलेंट्स और हैंगिंग प्लांट्स का डिस्प्ले।
- वुडन पैनल्स और लाइटिंग के साथ ग्रीनरी को सजाते हुए।

### 6. बच्चों के खेलने की जगह

- छोटे कुशन, खिलौनों का बॉक्स और रंग-बिरंगी दीवारें।
- बच्चों के खेलने के लिए एक मस्तीभरा कोना।

### 7. पालतू जानवरों के लिए कोना

- सीढ़ियों के नीचे पालतू जानवरों का बिस्तर और उनके खाने-पीने की चीजें व्यवस्थित तरीके से।
- उनकी पसंदीदा चीजों जैसे खिलौनों और चबाने वाली हड्डियों को भी शामिल करें।

### 8. वाइन स्टोरेज या बार काउंटर

- स्टाइलिश वाइन रैक और बार काउंटर।
- ग्लास होल्डर्स और बैकलिट लाइटिंग के साथ एलिगेंट लुक।

ये भी पढ़ें- इ्रुह्यह्नह्व अद्धक्ष्ह्य- घर में इन जगहों पर भूलकर भी न रखें पैसे, हो सकती है धन हानि

### 9. डिस्प्ले यूनिट या गैलरी

- आर्ट पीस और तस्वीरों के साथ वॉल-माउंटेड डिस्प्ले यूनिट।
- स्पॉटलाइट्स के साथ हर डिस्प्ले को हाइलाइट करते हुए।

### 10. छोटे गेस्ट रूम का विकल्प

- सिंगल बेड और वॉल-माउंटेड फर्नीचर के साथ एक कॉम्पैक्ट गेस्ट रूम।
- हल्के रंगों और अच्छे लाइटिंग से इसे अधिक खुला और आरामदायक दिखाएं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय

प्रमुख समाचार

## दिल्ली को मिलेगी फर्जी गारंटी से मुक्ति : पीयूष गोयल

**नईदिल्ली।** केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर दिल्ली की जनता से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन सरकार विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता देगी। गोयल ने बजट में मध्यम वर्ग को महत्वपूर्ण राहत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की और कहा कि दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत निश्चित लगती है। उन्होंने घोषणा की कि मोदी के नेतृत्व में, दिल्लीवासी विश्वसनीय नेतृत्व और विकास पहलों से प्रेरित सरकार की उम्मीद कर सकते हैं। यह कहते हुए कि आप के भीतर टूटन स्पष्ट है, गोयल ने कहा कि आगामी चुनावों से पहले आठ आप विधायकों के इस्तीफे ने पार्टी की घटती एकता का संकेत दिया है। उन्होंने उनके प्रतीक, झाड़ू की छड़ी, के रूपक का प्रयोग किया, जो प्रतीकात्मक रूप से बिखरा हुआ था।

## वह कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है : केजरीवाल

**नईदिल्ली।** दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम दिन आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने डबल इंजन सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से दिल्ली चुनाव में गुंडागर्दी हो रही है, देश की जनता जानना चाहती है कि यह कौन कर रहा है और सबसे बड़ा गुंडा कौन है। केजरीवाल ने भाजपा पर वार करते हुए पूछा कि आप कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, पुलिस असहाय है। वह कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है। केजरीवाल ने कहा कि रविवार को पहली बार ऐसा हुआ कि पत्रकारों पर हमला हुआ और एक का सिर काट दिया गया। कवरेज करने गए पत्रकारों को निकाल दिया गया। ये सब देश की संसद से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, ऐसा लगता है जैसे चुनाव आयोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

## डबल इंजन की सरकार ही ला सकती है बदलाव : चंद्रबाबू

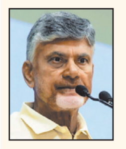

**नईदिल्ली।** दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि आप के नेतृत्व वाली सरकार का मॉडल विफल हो गया है और लोगों को ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए जो समावेशी विकास की ओर ले जा सके। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि लोग मौसम और राजनीतिक प्रदूषण के कारण दिल्ली में रहने को लेकर चिंतित हैं। 5 फरवरी को दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने रविवार को अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि आप की हाफ इंजन वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को बर्बाद कर दिया है और केवल भाजपा के नेतृत्व वाली डबल इंजन वाली सरकार ही इसे बचा सकती है। प्रदूषण की बढ़ती समस्या के लिए आप प्रमुख को जिम्मेदार ठहराते हुए नायडू ने कहा, यमुना सबसे प्रदूषित नदी है। 10 साल में आप प्रदूषण को नियंत्रित नहीं कर पाए।

## सरकार बनते ही तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलेंगे

**नईदिल्ली।** नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने सोमवार को कहा कि अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता में आई तो तालकटोरा स्टेडियम का नाम वाल्मिकी के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तालकटोरा एक स्टेडियम है और इसका नाम मुगल काल में दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि जब 8 फरवरी के बाद एनडीएमसी परिषद की बैठक होगी, तो इस स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मिकी करने का प्रस्ताव प्रस्तावित और पारित किया जाएगा। प्रवेश वर्मा ने कहा कि मैंने वादा किया था कि नतीजे घोषित होने के बाद एनडीएमसी की पहली बैठक में मैं प्रस्ताव रखूंगा और इसे पारित कराऊंगा, जिसके बाद एक महीने में स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि वाल्मिकी स्टेडियम कर दिया जाएगा। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आगे कहा कि यह चुनाव दिल्ली को बचाने का है। अरविंद केजरीवाल ने आपको क्या दिया है?

## महाकुंभ भगदड़ पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

**नईदिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट ने महाकुंभ में हुई भगदड़को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने तिवारी से कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और चिंता का विषय है, लेकिन उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। एक न्यायिक आयोग का गठन पहले ही किया जा चुका है। राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच चल रही है। उन्होंने उच्च न्यायालय में दायर एक ऐसी ही याचिका की ओर भी इशारा किया। सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय पैनल घटना की न्यायिक जांच कर रहा है।

### विपक्ष के हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की दो टूक

# जनता ने अगर नारेबाजी के लिए भेजा है तो यही करिए या सदन चलाइए

**नई दिल्ली।** बजट सत्र के तीसरे दिन सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वे महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर सरकार से जवाब की मांग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में नारेबाजी करने वाले विपक्षी दलों के सांसदों से कहा कि यदि जनता ने उन्हें नारे लगाने के लिए भेजा है जो यही काम करें या फिर कार्यवाही चलने दें।

दरअसल, बजट सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना पर सरकार से जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से कहा, इस विषय का उल्लेख राष्ट्रपति महोदया ने अपने अभिभाषण में किया था। आप लोग अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह विषय रख सकते हैं।

उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, जिसमें सरकार की जवाबदेही तय की जा सकती है। बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील की। समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य जब आसन के निकट पहुंचकर नारेबाजी करने लगे तो बिरला ने कहा, आपको जनता ने मेज तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। प्रश्न पूछने के लिए भेजा है। अगर इसीलिए भेजा है तो जोर-जोर से मारिए।

उन्होंने कहा, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी के लिए भेजा है तो यही काम करिए। यदि सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। उन्होंने प्रश्नकाल के बाद विपक्षी सदस्यों से कहा कि मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जिन भी विषयों को उठाना चाहते हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा में उन सभी को उठा सकते हैं। आपको पर्याप्त समय और अवसर दिया जाएगा।

बिरला ने कहा कि कई मंचों पर यह निर्णय हुआ है कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए, यह सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अन्य मुद्दे प्रश्नकाल के बाद उठाए जाने की परंपरा कायम की जानी

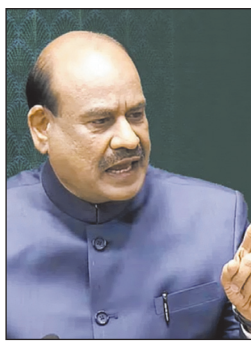

चाहिए। उन्होंने हंगामा करने वाले सांसदों से कहा, %हम संकल्प लें कि प्रश्नकाल कभी स्थगित न हो। यह मेरा आग्रह है। यदि आप नारेबाजी करने आए हैं, संसद को नियोजित तरीके से स्थगित कराने आए हैं, मेजें थपथपाने आए हैं तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। मैं आग्रह ही कर सकता हूं।%

विपक्षी दलों के सदस्यों ने 'प्रधानमंत्री जवाब दो' और 'शेम शेम' के नारे लगाए। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने इस घटना में मृतकों का सही आंकड़ा नहीं बताया।

इससे पहले संसद के निचले और ऊपरी दोनों सदन में ही जमकर हंगामा हुआ। इस वजह से बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही बाधित हुई। विपक्षी सांसद महाकुंभ भगदड़ की घटना समेत कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। राज्यसभा में दूसरे दिन की कार्यवाही भी शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सभी सांसद राज्यसभा से बाहर चले गए। बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी तक जारी रहेगा और दोनों सदन 4 अप्रैल को सत्र के समापन के साथ अवकाश के बाद 10 मार्च को फिर से मिलेंगे।

### लोकसभा में भाजपा सांसद का दावा महाकुंभ हादसे में साजिश की बू...

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए चर्चा में भाग लिया। रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा तथा उनके 'राजनीतिक डीएनए' में है।

भाजपा नेता ने कहा कि राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं और संसद का हिस्सा हैं। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें। राष्ट्रपति जी बहुत ही साधारण परिवार से निकलकर आगे बढ़ीं। पिछले दो वर्षों में वह गरिमा और शालीनता से राष्ट्रपति के पद को नई ऊंचाई दे रही हैं। उनके मुताबिक, शायद पहली बार राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी कर किसी बयान का खंडन किया गया है। प्रसाद ने सोनिया गांधी की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, ''मैं इस टिप्पणी की भर्त्सना करना चाहता हूं।'' उन्होंने कहा कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या-क्या व्यवहार किया गया था, उसकी जानकारी दस्तावेजों में अंकित है। प्रसाद के अनुसार, फखरूद्दीन अली अहमद और ज्ञानी जैल सिंह जैसे पूर्व राष्ट्रपति के साथ क्या व्यवहार किया गया, सबको पता है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल की मृत्यु 1950 में हो गई लेकिन उन्हें 1991 में भारत रत्न दिया गया। एक को छोड़कर सभी 550 रियासतों का प्रबंधन सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया। सिर्फ एक रियासत कश्मीर को जवाहरलाल नेहरू ने संभाला था और उसे संभालने के लिए पीएम मोदी को आना पड़ा था और आज वहां चुनाव हो रहे हैं। महाकुंभ में हुई भगदड़ पर प्रसाद ने कहा कि घटना की जांच चल रही है। जांच से हमें साजिश की बू आ रही है। जब पूरी जांच होगी तो घटना के पीछे जो लोग थे उन्हें शर्म से झुकना पड़ेगा। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय भारत पांच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की सूची में शामिल था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई तथा पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई।

### अमित शाह का केजरीवाल पर वार

# मोदी की गारंटी मतलब पत्थर पर खींची लकीर

**नईदिल्ली।** दिल्ली चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा में चुनावी रैली को संबोधित किया। शाह ने हुंकार भरते हुए कहा कि 8 फरवरी को दिल्लीवाले आप-दा सरकार को झाड़ू लगाकर बाहर फेंकने वाले हैं। आप और अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए अमित शाह ने सवाल किया कि 10 वर्षों तक, अनेक वादे कर केजरीवाल और उनके चट्टे-बट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया, तुष्टिकरण दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप और केजरीवाल ने दिल्ली को धोखा दिया है।

अमित शाह ने जंगपुरा से आप प्रत्याशी और आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा कि देशभर में एक ही शिक्षा मंत्री है, जो शराब घोटाला मामले में जेल गया है। शिक्षा मंत्री का काम होता है, बच्चों को शिक्षा देना, स्कूल बनाना, शिक्षकों का कल्याण करना, नए कॉलेज बनाना। ये सब तो कुछ उन्होंने (मनीष सिसोदिया) किया नहीं, बल्कि दिल्ली में गली-गली में शराब की दुकानें खोली हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भाजपा एक अकेली ऐसी पार्टी है, जो कहती है वो करती है। मोदी की गारंटी मतलब पत्थर पर खींची लकीर।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 में भाजपा ने वादा किया था कि हम इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर देंगे। 10 साल के अंदर इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 31 मार्च, 2026 तक हम इस देश से नक्सलवाद को भी समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि हम जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाएंगे। केजरीवाल जी, राहुल बाबा, अखिलेश, ममता जी... इन सभी ने विरोध किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटाओगे तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी।

शाह ने कहा कि मोदी जी ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। खून की नदियां छोड़ो किसी की पत्थर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने

कहा कि इन लोगों ने (आम आदमी पार्टी) वादा किया था कि हम यमुना जी के पानी को साफ करेंगे। केजरीवाल जी, आपने तो यमुना जी को स्वच्छ नहीं किया, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बना दीजिए, तीन साल में हम यमुना रिवर फ्रंट बनाने का काम करेंगे।

### छात्रों के भविष्य से खेल रही दिल्ली की आप सरकार : मोदी

दिल्ली चुनाव को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे आम आदमी पार्टी सरकार की छवि सुधारने के लिए छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली में सुना है, वे (आप सरकार) बच्चों को 9वीं कक्षा के बाद आगे नहीं जाने देते हैं। केवल उन्हीं बच्चों को जाने की अनुमति दी जाती है जिनके पास होने की गारंटी होती है। क्योंकि अगर उनका रिजल्ट ख़राब आया तो उनकी सरकार की साख ख़राब हो जायेगी। इसलिए बहुत बेईमानी का काम किया जाता है। चूंकि दिल्ली चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी 5 फरवरी को अपनी अगली सरकार चुनने के लिए मतदान करेगी, राजनीतिक नेता और पार्टियां लोगों का दिल जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरके पुरम में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और मोदी की गारंटी के अपने चुनावी नारे को दोहराया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट में मध्यम वर्ग समर्थक प्रावधानों को दोहराया। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग कह रहा है कि यह भारत के इतिहास में उनके लिए सबसे अनुकूल बजट है।

खेल

प्रमुख समाचार

## टी20 के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज, 6,9 और 12 को होंगे मैच

**नईदिल्ली।** टीम इंडिया ने 5 मैचों की टी20 सीरीज पर 4-1 से कब्जा कर लिया है। अब भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी। पहला मैच 6 फरवरी से नागपुर में है। 9 और 12 फरवरी को कटक और अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अंतिम मुकाबला होगा। घरेलू मैदान पर लगातार 17वीं टी20 सीरीज जीत हासिल करके इंग्लैंड के खिलाफ टी20 जीत की लय को बरकरार रखने के बाद टीम तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज के लिए अंग्रेज टीम की मेजबानी करने के लिए तैयार है।

1. पहला वनडे: छह फरवरी, वीसीए स्टेडियम, नागपुर, 1.30 बजे दोपहर।
2. दूसरा वनडे: नौ फरवरी, बाराबती स्टेडियम, कटक, 1.30 बजे दोपहर।
3. तीसरा वनडे: 12 फरवरी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, 1.30 बजे दोपहर।

मेन इन ब्लू ने 2024 में केवल तीन एकदिवसीय मैच खेले थे। उन्होंने एक टाई खेला और दो हारे थे। आखिरी बार 2023 वनडे विश्व कप सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पर जीत के रूप में एकदिवसीय मैच जीता था। रोहित शर्मा की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इस सीरीज को जीतना चाहेगी और 2024 को भूल करना आगे बढ़ेगी।

**इंग्लैंड की वनडे टीम :** जोस बटलर (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्से, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल राशिद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल साल्ट, मार्क वुड।

**भारतीय टीम:** रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत ,रविन्द्र जड़ेजा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

## सेंसेक्स 319 अंक टूटा निफ्टी 23,400 के नीचे बंद

**नईदिल्ली।** घरेलू शेयर बाजार सोमवार (3 फरवरी) को सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन में गिरावट लेकर बंद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के कनाडा, मेक्सिको और चीन से आयात पर टैरिफ शुल्क बढ़ाने के फैसले के बाद वैश्विक बाजारों में गिरावट आई। डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट ने भी निवेशकों के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स सोमवार (3 फरवरी) को लगभग 500 अंक की गिरावट लेकर 77,063 पर खुला। कारोबार के दौरान यह 900 से ज्यादा अंक की गिरावट लेकर 76,756 तक फिसल गया था। अंत में सेंसेक्स 319.22 या 0.41% की गिरावट लेकर पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी50 भी खुलते ही 23 हजार के नीचे फिसल गया। अंत में कुछ रिकवरी करते हुए निफ्टी 121 अंक या 0.52त्न फिसलकर 23,361 पर क्लोज हुआ।

## इंजीनियर्स इंडिया को मिला 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट

**नईदिल्ली।** सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर की नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को राष्ट्रीय महत्व के एक शैक्षणिक संस्थान के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मिला है। इस बड़े ऑर्डर के बाद शेयर में हल्की रिकवरी देखी गई लेकिन चौतरफा बिकवाली के दबाव में शेयर फिसल गया। यह नवरत्न पीएसयू स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई से करीब 45 फीसदी गिरावट पर कारोबार कर रहा है। इंजीनियर्स इंडिया ने सोमवार को शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि उसे राष्ट्रीय महत्व के एक शैक्षणिक संस्थान के डेवलपमेंट के लिए 1200 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी ने प्रोजेक्ट की गोपनीयता के चलते इसकी डीटेल साझा नहीं की है। इंजीनियर्स इंडिया के शेयर में सोमवार (3 फरवरी) गिरावट के साथ 167.70 रुपये पर कारोबार की शुरुआत हुई।

## जनवरी में एक्सपोर्ट और नए ऑर्डर ने दिया उछाल

**नईदिल्ली।** जनवरी में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दमदार शुरुआत की है। दिसंबर में थोड़ी सुस्ती के बाद अब एक्सपोर्ट्स में करीब 14 साल की सबसे तेज बढ़त देखने को मिली है। नए ऑर्डर्स भी जुलाई के बाद सबसे तेज रफ्तार से बढ़े हैं। इस वजह से जनवरी का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) छह महीने के टॉप लेवल पर पहुंच गया है। एचएसबीसी और एसएंडपी ग्लोबल द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार, जनवरी में पीएमआई 57.7 रहा, जबकि दिसंबर में यह 56.4 था। बता दें कि पीएमआई का 50 से ऊपर होना सेक्टर में ग्रोथ को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा गिरावट को दिखाता है। जबरदस्त एक्सपोर्ट्स और ऑर्डर्स की इस तेजी से भारतीय प्रोड्यूसर्स ने नए साल की मजबूत शुरुआत की है, जो आगे भी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है।

## नया इनकम टैक्स बिल लाने की तैयारी में सरकार

**नईदिल्ली।** केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रमुख रवि अग्रवाल ने सोमवार को उद्योग जगत से नए आयकर विधेयक पर अपने सुझाव देने को कहा। यह विधेयक इस सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। नया आयकर विधेयक छह दशक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान ले सकता है। इसे छह महीने के भीतर तैयार किया गया है। करदाताओं के लिए कर अनुपालन को सुगम तथा इसे पढ़ने व समझने में आसान बनाने के लिए भाषा को सरल रूप देने के प्रयास किए गए हैं। अग्रवाल ने कहा कि नया विधेयक इस तरह से तैयार किया गया है कि यह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। इसके अलावा, नए कानून को संक्षिप्त बनाया गया है क्योंकि पुराने प्रावधानों को हटा दिया गया है, जिससे यह कम बोझिल हो गया है।

# क्या भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा

(गतांक से आगे...)

**प्रह्लाद सबनानी**

आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम लम्बे समय तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। कई बार तो सुधार कार्यक्रम सम्बंधी कानून बनाने के बाद उन्हें लागू करने में भी लम्बा समय लग जाता है। जैसे भारत में 4 श्रम कोड वर्ष 2019-2020 के बीच में संसद द्वारा पास किए गए थे परंतु इन कोड को अभी भी लागू नहीं किया जा सका है।

हालांकि वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं परंतु अभी भी कई क्षेत्रों में काम किया जाना शेष है। जैसे, भारत में पूंजी आज भी बहुत अधिक ब्याज दर पर उपलब्ध हो पाती है, हालांकि ऋण प्रदान करने सम्बंधी नियमों को शिथिल बनाया गया है, परंतु पूंजी की लागत बहुत अधिक है। भारत में युवा जनसंख्या अच्छी तादाद में है, आज भारत के नागरिकों की औसत आयु केवल 29 वर्ष है जो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। यह भारत के लिए यह लाभदायक स्थिति है परंतु भारत आज भी इस स्थिति का लाभ नहीं उठा पा रहा है। इस प्रकार के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर भारत में अभी भी बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है।

भारत को अभी भी आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारे देश की मजबूती किन क्षेत्रों में हैं इन क्षेत्रों को चिन्हित कर हमें उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे उत्पादकता के मामले में अन्य देशों, विशेष रूप से पश्चिमी देशों, की तुलना में हम अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। उत्पादकता कम होने के चलते भारत में निर्मित उत्पादों की लागत अधिक रहती है।

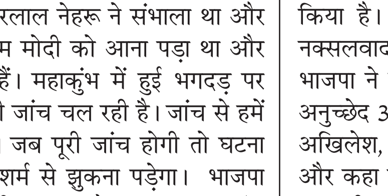

देश में करों की दर (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है, इसे कम करने के सम्बंध में गम्भीरता से विचार करने की आज महती आवश्यकता है। साथ ही, बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे ऋण पर ब्याज की दर भी बहुत अधिक है, इससे भी उत्पादन लागत में वृद्धि होती है और भारत में निर्मित उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक लागत के चलते टिक नहीं पाते हैं। अत: अब समय आ गया है कि ब्याज दरों को कम करने के बारे में भी गम्भीरता से विचार हो।

देश में हर समय कहीं न कहीं चुनाव हो रहे होते हैं और कई बार तो देश के बहुत बड़े भू भाग पर चुनाव आचार संहिता के लागू होने के चलते केंद्र एवं राज्य सरकारों को अपने पूंजीगत खर्चे रोकने होते हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अत: देश में वन नेशन वन इलेक्शन को भी लागू करने की महती आवश्यकता है। साथ ही, आजकल कुछ राज्य सरकारों के बीच नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की जैसे होड़ ही लग गई है। मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराने से इन प्रदेशों के बजट पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न होता है। अत: इस प्रकार के खर्चों पर रोक लगाए जाने की भी आज आवश्यकता है। भारत की आर्थिक विकास दर को 10 प्रतिशत से भी ऊपर ले जाया जा सकता है यदि हिंदू सनातन संस्कृति की अर्थव्यवस्था को भारत में बढ़ावा दिया जाय। इसके लिए देश के ब्यूरोक्रेसी के सोच में परिवर्तन लाना भी आवश्यक है। भारत में भव्य मंदिरों का निर्माण कर एवं इन स्थानों पर अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए धार्मिक पर्यटन को जबरदस्त बढ़ावा दिया जा सकता है। इससे होटल उद्योग, परिवहन उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बहुत लाभ होगा एवं रोजगार के करोड़ों नए अवसर भी निर्मित होंगे। देश में शादियों के मौसम में लाखों करोड़ रुपए का खर्च होता है तथा विभिन्न त्यौहारों पर भी भारतीय नागरिकों के खर्च में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इस सबका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक रहता है, अत: शादियों के मौसम एवं विभिन्न त्यौहारों पर नागरिकों को सरकार द्वारा विशेष सुविधाएं प्रदान करने से विभिन्न उत्पादों की खपत में वृद्धि की जा सकती है। और, अंतत: यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करने में सहायक होगा। अत: हिंदू सनातन संस्कृति के संस्कारों को देश में लागू करने के संदर्भ में अब देश के ब्यूरोक्रेसी को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

# गहिरा गुरु महाराज के उपदेशों से आदिवासी समाज को मिला सत्य सनातन धर्म का बोधः सीएम साय

### श्रीकोट आश्रम में गुरुमाता पूर्णिमा जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री

**रायपुर।** यह हम सभी के लिए अत्यधिक गौरव का विषय है कि हम इस पवित्र स्थल पर एकत्रित होकर परम पूज्य संत गहिरा गुरु जी और माता पूर्णिमा जी के योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि माता पूर्णिमा जी का जीवन पूरी तरह से त्याग, तपस्या और समाज सेवा की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करता है। उनका विग्रह समाज के कल्याण के प्रति उनके अडिग समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज श्रीकोट आश्रम बलरामपुर में परम पूज्य संत गहिरा गुरु की धर्मपत्नी पूर्णिमा जी के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा के विशेष अवसर पर यह बात कही।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि संत गहिरा गुरु जी ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी समाज की सेवा का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने दीन-हीन और असहायों की सेवा को अपना परम धर्म माना और सत्य, शांति, दया और क्षमा के सिद्धांतों को धर्म के अमूल्य स्तंभ के रूप में स्थापित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने संत गहिरा गुरु जी द्वारा आदिवासी समुदायों के उत्थान में दिए गए अतुलनीय योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी और उन्हें आह्वान किया कि वे माता पूर्णिमा जी और संत गहिरा गुरु जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हुए समाज को एक नई दिशा देने हेतु मनोयोग से जुट जाएं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यहां आने पर मुझे माता के विग्रह के दर्शन सौभाग्य मिला, उनका सजीव और मनोरम विग्रह देखकर ऐसा लगा मानो किस क्षण वह बोल उठे। श्री साय ने गहिरा गुरु जी का स्मरण करते हुए कहा कि गहिरा गुरु जी आदिवासी समाज के बड़े संत हुए, जिनके उपदेशों और कथनों के जरिए पूरे समाज ने सत्य सनातन धर्म का महत्त्व जाना। उन्होंने कहा कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से पिछड़े हुए आदिवासी समुदाय के जीवन में गहिरा गुरु महाराज के उपदेशों से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सुधार आया।

साय ने कहा कि मेरा सौभाग्य रहा कि गहिरा गुरु समाज का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। रायगढ़ के सांसद रहते गहिरा गुरु महाराज के जन्म ग्राम को गोद लेकर उसका विकास करने का सौभाग्य मिला। आज उनके आदर्शों को आत्मसात कर समाज आगे बढ़ रहा है। जगह-जगह संस्कृत महाविद्यालय खुल रहे हैं और आदिवासी समाज लगातार आगे बढ़ रहा है। समारोह में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

## वार्डों में ईव्हीएम की जीवंत प्रदर्शनी

**बिलासपुर।** नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2025 के तहत लोगों को ईव्हीएम मशीन की जानकारी देने विभिन्न वार्डों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए वार्डवार मास्टर ट्रेनर नियुक्त किये गये हैं जो ईव्हीएम मशीन की जीवंत प्रदर्शनी से लोगों को मतदान की प्रक्रिया और तकनीकी बारीकियों से अवगत कराएंगे। सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक ईव्हीएम की जीवंत प्रदर्शनी वार्डों में लगाई जाएगी। आज 4 फरवरी 2025 जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 साई नगर के पौनी पसारी हॉफा चौक के पास उस्लापुर, वार्ड क्रमांक 4 गोकुल नगर महामाया चौक, जोन क्रमाक 2 के वार्ड क्रमांक 7 कलिका नगर हेतु विष्णु चौक के पास, वार्ड क्रमांक 8 चित्रकांत जायसवाल नगर मन्नाडोल सामुदायिक भवन के पास, जोन क्रमांक 3 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 नेहरू नगर में किया गया।

## मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

# यह कैसा लोकतंत्र है?

अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना इसी को तो कहते हैं. प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई. उस पर एक टीवी चैनल का रिपोर्टर समाचार बना रहा था, तो उसे वहां के कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की. यहां तक कि उसे धक्के मार कर बाहर निकला गया. वह रिपोर्टर मौत के आंकड़ों पर सवाल उठा रहा था और उसे रोका जा रहा था. इस देश में लोकतंत्र है. अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है. यही तो है अभिव्यक्ति की आजादी कि जो सच है, वह दिखाया जाए. रोज चैनल वाले यह दिखा रहे हैं कि 30 करोड़ आ गए 35 करोड लोगों ने संगम में स्नान कर लिए. इतना प्रमाणिक आंकड़ा आपको रोज मिल रहा है.लेकिन जो लोग भगदड़ में मर गए, उनके आंकड़े प्रशासन क्यों छिपा रहा है. आखिर इतनी पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए कि कितने लोग मरे. अगर कोई पत्रकार जानना चाहता है, तो उसे जानने का पूरा अधिकार है.उसे रोकने का मतलब है कि आप कहीं न कहीं कुछ छुपा रहे हैं. यह अपने आप में अपराध है. पत्रकारिता के शाश्वत मूल्यों पर प्रहार है. लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि हमारे पूरे सिस्टम में कथनी करने का अंतर है. जो सच है, वह दिखाया जाना चाहिए. इसमें किसी को बुरा नहीं लगेगा. क्योंकि यह भगदड़ सहज रूप में उभर कर सामने आई. हालांकि भगदड़ के पीछे एक कारण तो लोगों का धैर्य खो देना भी है. दूसरा कारण यह है कि मेला स्थल में वी वीआईपीयों के लिए एक अलग रास्ता बनाया गया और सामान्य लोगों के लिए दूसरा रास्ता. इस देश में आखिर इतना वर्ग भेद क्यों होता है? क्यों इस देश के चंद लोग वीवीआईपी माने जाते हैं और एक बड़ी आबादी के लोग कीड़े-मकोड़े? अकसर धार्मिक स्थलों में इस तरह का अपराध देखने को मिलता है. मैं कई बार यह नहीं समझ पाता कि अगर वीवीआईपी भगवान के पहले दर्शन कर लेगा तो क्या भगवान उसे कुछ ज्यादा आशीर्वाद प्रदान कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बस उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि वह बड़ा आदमी, नेता या अफसर है. ऐसी विषमता देखकर धर्म स्थलों में लोगों को बहुत गुस्सा आता है. कायदे से तो इस देश में यह वीवी आई पी-संस्कृति ही खत्म होनी चाहिए. भगवान के दर पर क्या राजा, क्या गरीब, सब बराबर हैं . लेकिन यहां भी भेद किया जाता है. इस देश में सच्चा लोकतंत्र तब आएगा, जब एक आम आदमी भी भीड़ में खड़ा हो और उसके ठीक पीछे या आगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री या कोई बड़ा अफसर. सबके लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए. हां जो वीवीआई पी हैं,उनकी सुरक्षा के लिए अगल-बगल कमांडो आदि तैनात रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन उन्हें खड़ा होना चाहिए आम लोगों की कतार में. पर ऐसा होता कहां है. दुनिया के अनेक देशों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि के लिए बहुत अधिक प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता. सामान्य लोगों की तरह ही वे आना-जाना करते हैं. लेकिन हमारे यहां दिक्कत यह है कि सदियों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ तो कुछ लोगों के दिमाग से अभी भी राजशाही का भूत नहीं उतरा है. वे चुने हुए प्रतिनिधि को राजा समझ बैठते हैं. उनकी व्यवस्था में लगे लोग उनको राजा महाराजा बनाकर व्यवहार करते हैं. आम लोगों को जनप्रतिनिधियों से दूर कर दिया जाता है. उन्हें धक्का मारा जाता है.. उन पर लाठियां बरसाई जाती है. इस देश में यह विषमतावादी लोकतंत्र आखिर कब तक चलेगा? इस पर विचार करना चाहिए. और अगर महाकुंभ में ज्यादा मौतें हुई हैं,तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं. सच को सामने आने देना चाहिए. ऐसा करके हम अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करेंगे और लोकतंत्र को लोकतंत्र बने रहने देंगे, उसे राजतंत्र नहीं बनाएंगे.

# निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने मैदान में उतरे सांसद बृजमोहन

रायपुर।भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को आरंग विधानसभा क्षेत्र के मंदिर हसौद और समोदा में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर हसौद नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी संदीप जोशी, आरंग नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रत्याशी डॉ. संदीप जैन और समोदा नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी छोटेलाल सोनकर समेत सभी भाजपा पार्षद प्रत्याशियों को विजयदिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया।

सभा को संबोधित करते हुए सांसद अग्रवाल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश और संकल्प इस बात का प्रमाण है कि नगर निकायों में विकास और सुशासन की गूंज एक बार फिर सुनाई देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'सबका साथ, सबका विकास' के संकल्प को साकार करने के लिए भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटा हुआ है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर उन्हें भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताकर आगामी चुनाव में भाजपा को पुनः विजय दिलाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि , क्षेत्र का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। लोग ऐसे नेताओं से सावधान रहें जो केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं और भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करें जो लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं।उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र में भाजपा को मिल रहा अपार समर्थन यह सुनिश्चित करता है कि आगामी नगर निकाय और पंचायत चुनावों में भाजपा प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करेगी और सुशासन का कमल खिलेगा।

इस अवसर पर विधायक गुरू खुशवंत साहेब, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष श्याम नारंग, पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय, मंडल अध्यक्ष गोपाल वर्मा, ओम प्रकाश देवांगन, कृष्णा वर्मा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

# ईडी ने तिवारी, रानू, सौम्या, समीर के 55.37 करोड़ की कई चल और अचल संपत्तियां की कुर्क

**रायपुर।** प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय से जारी एक बयान में कहा है कि जेल में बंद आईएएस श्रीमती रानू साहू,, आईएएस समीर बिश्नोई, तत्कालीन मुख्यमंत्री की तत्कालीन ओएसडी सौम्या चौरसिया और विनोद तिवारी की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत 30/01/2025 को बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन सहित 100 से अधिक चल और अचल 55.37 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया।

ईडी ने जारी बयान में कहा है कि कोयला घोटाले में जेल में बंद कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी की मूल्य 49.73 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है। ईडी के मुताबिक जांच में पता चला है कि निजी व्यक्तियों का एक समूह, राज्य के वरिष्ठ राजनेताओं और नौकरशाहों के साथ मिलीभगत करके, कोयला ट्रांसपोर्टरों से जबरन वसूली की थी। उन्होंने जुलाई 20- जून 2022 के बीच परिवहन किए गए कोयले के प्रति टन 26 रुपये का शुल्क लिया। इस अवधि के दौरान, अपराध की कुल आय (पीओसी) 540 करोड़ रुपये (लगभग) थी, जो छत्तीसगढ़ में कोयला ट्रांसपोर्टरों से वसूली गई थी। अवैध धन का इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं को रिश्वत देने के लिए किया गया था, पीओसी का कुछ हिस्सा चुनावों में भी खर्च किया गया था। शेष धनराशि का उपयोग विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया था।

लगभग 55.37 करोड़ रुपये की कई चल और अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, जो श्रीमती रानू साहू, आईएएस, समीर बिश्नोई, आईएएस कछत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री की तत्कालीन ओएसडी सौम्या चौरसिया, आईएएस जय प्रकाश मौर्य और राम गोपाल अग्रवाल, राम प्रताप सिंह, विनोद तिवारी, चंद्र देव प्रसाद राय, देवेंद्र सिंह यादव, सभी राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति थे। चल रही जांच के तहत ईडी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और 25 आरोपियों के खिलाफ विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं, जिसने दायर शिकायतों का संज्ञान लिया है। इसके अलावा, आरोपी व्यक्तियों की 270 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही आज तक जब्त की जा चुकी है, आगे की जांच जारी है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

## छात्राओं को मुफ्त सैनेटरी पैड का चुनावी वादा

**रायपुर।** कांग्रेस महापौर प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे ने अपने सघन जनसंपर्क के दौरान कहा कि वे सामाजिक कार्यों को लंबे समय से देख रही हैं। ऐसे में देखने में आ रहा है कि परिवार और समाज में घरेलू हिंसा बढ़ रही है, जिसे कानून से ज्यादा काउंसलिंग के जरिए सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे इस दिशा में कार्य करेंगी ताकि महिलाओं को न्याय और सुरक्षा मिले। जनसंपर्क के दौरान दीप्ति प्रमोद दुबे को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि शहर के विकास के लिए कांग्रेस का समर्थन करें। साथ ही, उन्होंने छात्र-छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने का वादा किया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर शहर के विभिन्न वार्डों में संगठनात्मक बैठकें एवं विशाल जनसंपर्क अभियान भी आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं और जनता का भारी समर्थन देखने को मिला। पहली बैठक वार्ड क्रमांक 15 के दहीहांडी मैदान में हुई, जिसमें वार्ड 15, 17, 18, 19, 20 और 26 के पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में रुकमणी सुंदर जोगी, दिलेश्वरी साहू, जीतेंद्र साहू, वरन साहू और घ्यांश्याम देवांगन उपस्थित रहे।

## किस नैतिकता से नये वादे कर रही भाजपाः शुक्ला

**रायपुर।** राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने जनता को ठगने के लिए नगरीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र जारी किया था उसे पूरा नहीं कर पाये। जनता का भरोसा उठ गया है तब अटल जी के नाम से अटल विश्वास पत्र जारी कर रहे। भाजपा को पता है मोदी के नाम से जनता वोट नहीं देगी "मोदी की गारंटी" फिर नहीं चलेगी। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती इसीलिये नगरीय निकाय के घोषणा पत्र को 'अटल विश्वास पत्र' का नाम दिये है लेकिन जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली।विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र के रूप में मोदी की गारंटी प्रस्तुत किया। मोदी की गारंटी में कुल 20 वादे किये थे, 1 साल हो गये राज्य में भाजपा की सरकार बने मोदी की गारंटी के 20 गारंटी में से 17 गारंटी आज भी पूरे नहीं किये जो 3 गारंटी पर जो कुछ काम हुआ है वह भी आधा अधूरा है। जब पहले के वादे पूरे नहीं किये फिर किस नैतिकता से फिर जनता के सामने नया घोषणा पत्र लेकर आये है। जब पुराना घोषणा पत्र जिसके आधार पर 2023 में राज्य में सरकार चलाने का जनादेश लिया उसे पूरा नहीं किया।

## सूर्यकांत तिवारी की 50 करोड़ की संपत्तियां अटैच

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई करते हुए व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी की लगभग 50 करोड़ रुपये की संपत्ति को अटैच कर लिया है. ईडी ने सूर्यकांत तिवारी की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है. इसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नगदी, आभूषण और जमीन शामिल हैं. यह कार्रवाई कोयला लेवी वसूली मामले में की गई है, जिसमें सूर्यकांत तिवारी पहले से ही जेल में बंद हैं. ईडी ने इस संबंध में एक्स पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी है.ईडी ने अपने ट्वीट में कहा, ईडी रायपुर ने अवैध कोयला लेवी घोटाले से संबंधित मामले में सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30/01/2025 को कुल मिलाकर 49.73 करोड़ रुपये मूल्य की 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल हैं. छत्तीसगढ़ में कथित 500 करोड़ रुपये के कोयला घोटाला मामले में लेवी वसूली का मामला ईडी की रेड में सामने आया था. आरोप है कि कोयला परिवहन के दौरान कोयला व्यापारियों से वसूली करने के लिए ऑनलाइन मिलने वाले परमिट को ऑफलाइन कर दिया गया था।

## कांग्रेस अब राजनीतिक दल नहीं गिरोह है : केदार कश्यप

**रायपुर ।** वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस के आरोप पत्र पर पलटवार करते हुए कहा ,वाह क्या खूब बेशर्मी है। 5 साल के कार्यकाल में जनता को धोखा देकर एक वादा पूरा न करने वाली कांग्रेस अब भाजपा के शासन के 1 साल में आरोप पत्र ला रही है। कश्यप ने कहा कि बेशर्म और बेहया कांग्रेस के ऐसे आरोपो को जनता एक सिरे नाकार चुकी है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद, कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई और उसके बाद फिर उपचुनाव में भी उसकी बड़ी भयंकर हार हुई। जनता ने बार-बार बता दिया है कि वह कांग्रेस की झूठी बातों में अब नहीं आएगी ।मंत्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से पहले अपराध करवा रही है और उसके बाद अपराध पर आरोप पत्र ला रही है अब तक जितने भी अपराध हुए हैं सारे अपराधों में कांग्रेसी नेताओं का हाथ सामने आ रहा है। कांग्रेस ने झूठा आरोप पत्र लाकर यह प्रमाणित कर दिया है की नगरी निकायों में उनके महापौरों ने कोई काम नहीं किया, नहीं तो वह अपनी उपलब्धियां लेकर सामने आते। कांग्रेस के किसी नेता के पास एक उपलब्धि बताने को नहीं हैं जो हश्र कांग्रेस का पहले हुआ। वहीं अब भी होगा कांग्रेस को नगरी निकाय चुनाव में करारी हार का सामना करना होगा।

## कृषि की दशा और दिशा बदलने वाला क्रांतिकारी बजटः डॉ. चंदेल

**रायपुर।** इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने केन्द्रीय बजट 2025-26 को देश में कृषि के विकास की दिशा में एक क्रान्तिकारी मदम बताया है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट विकासपरक, समावेशी एवं रोजगारोन्मुखी बजट है, जिससे भारत में कृषि की दशा और दिशा में वृहद परिवर्तन देखने को मिलेगा। डॉ. चंदेल ने कहा कि बजट में देश के 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे देश में कृषि उत्पादकता बढ़ेगी और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस योजना से 1.70 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि बजट में सब्सिडी वाले कृषि ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रूपये करने का प्रस्ताव है, जिससे 7.70 करोड़ किसानों, मछुवारों और पशुपालकों के लिए अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा मिलेगी। इस कदम से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में तीव्र वृद्धि होगे।डॉ. चंदेल ने कहा कि इस बार के बजट में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित कृषि अनुसंधान, विकास और नवाचार हेतु 20 हजार करोड़ रूपये का आबंटन किया गया है, जो एक अभुतपूर्व निर्णय है। इससे कृषि के क्षेत्र में निजी संस्थाओं द्वारा किये जा रहे अनुसंधान, विकास एवं नवाचारी प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

### मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेलमंत्री का आभार जताया

# छत्तीसगढ़ में 41 हजार करोड़ से हो रहा रेल सुविधाओं का विकास

### केन्द्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए 6925 करोड़ रूपए की सौगात

**रायपुर।** छत्तीसगढ़ में 41 हजार करोड़ रूपए की लागत से रेलवे सुविधाओं के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें रेल्वे ट्रैक का विस्तार, रेलवे लाईन का दोहरीकरण, रेलवे फ्लाई ओवर एवं ब्रिज आदि का निर्माण शामिल है। केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य में रेल्वे सुविधा के विकास के लिए 6925 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। इससे राज्य में रेल परियोजनाओं के कामों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के उन्नयन और विकास के लिए 41,000 करोड़ रुपए के निवेश से नई रेल लाइनों, रेलवे फ्लाईओवर और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में रेलवे का शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को अभूतपूर्व रेल परियोजनाओं की सौगात मिली है। ये परियोजनाएं राज्य के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी और जनता को बेहतर रेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय के कारण छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क विस्तार की ऐतिहासिक पहल हो रही है। इससे यात्री सुविधाओं में सुधार के साथ-साथ औद्योगिक, खनिज और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क विस्तार से न केवल यात्री परिवहन बल्कि खनिज संपदा और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में तेजी आएगी। इससे राज्य में व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

छत्तीसगढ़ में रेलवे के दीर्घकालिक विकास के लिए रावघाट-जगदलपुर, धरमजयगढ़-लोहरदगा और खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा जैसी कई नई रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को ऐतिहासिक रेलवे बजट प्राप्त हुआ है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और यात्री सुविधाओं को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस विकास यात्रा को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।गौरतलब है कि रावघाट रेलवे लाइन के अन्तर्गत दल्लीराजहरा-अंतागढ़ (77 किमी) सेक्शन चालू, यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। रावघाट तक विस्तार कार्य प्रगति पर, जिससे भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होगी और ग्रामीणों को किफायती यातायात सुविधा मिलेगी। इसी तरह के.के. रेल लाइन दोहरीकरण के अन्तर्गत 170 किमी में से 148 किमी का कार्य पूर्ण हो चुका है। इससे बस्तर और दंतेवाड़ा जिले की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। आवागमन आसान और माल परिवहन सुविधाजनक हो सकेगा। 4021 करोड़ रूपए की लागत वाली डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेल लाइन परियोजना की लंबाई 295 किमी है।

# सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में हुआ ईवीएम का रेंडमाईजेशन

**रायपुर ।** नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत आम चुनाव के परिपेक्ष्य में आज कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में सामान्य प्रेक्षक श्रीमती इफ्फत आरा की उपस्थिति में ईवीएम का रेंडमाईजेशन हुआ। जिसमें सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत में कुल 240 वार्ड में कुल 1290 मतदान केन्द्र शामिल हैं। इस प्रकार यहां के मतदान केन्द्र में 2390 बैलेट यूनिट एवं 1290 कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाए जाएंगें। साथ ही रिजर्व में 2140 बैलेट यूनिट और 610 कंट्रोल यूनिट रहेंगे।

नगर पालिक निगम रायपुर में 70 वार्ड में कुल 1095 मतदान केन्द्र हैं, यहां प्रति मतदान केन्द्र में 2 बैलेट यूनिट लगेगी। इस प्रकार यहां के मतदान केन्द्र में 2190 बैलेट यूनिट एवं 1095 कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाए जाएंगें। साथ ही रिजर्व में1260 बैलेट यूनिट और 225 कंट्रोल यूनिट रहेंगे। नगर पालिका परिषद आरंग में 17 वार्ड में 25 मतदान केन्द्र हैं। यहां प्रति मतदान केन्द्र में 1 बैलेट यूनिट लगेगी। इस प्रकार यहां के मतदान केन्द्र में 25 बैलेट यूनिट एवं 25 कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाए जाएंगें। साथ ही रिजर्व में 95 बैलेट यूनिट और 35 कंट्रोल यूनिट रहेंगे। नगरपालिका परिषद गोबरा-नवापारा में 21 वार्ड में 26 मतदान केन्द्र हैं। यहां प्रति मतदान केन्द्र में 1 बैलेट यूनिट लगेगी। इस प्रकार यहां के मतदान केन्द्र में 26 बैलेट यूनिट एवं 26 कंट्रोल यूनिट उपयोग में लाए जाएंगें। साथ ही रिजर्व में 114 बैलेट यूनिट और 44 कंट्रोल यूनिट रहेंगे। नगरपालिका परिषद तिल्दा में 22 वार्ड में 31 मतदान केन्द्र हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.